राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 11, अंक- 93 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरूवार ,07 अक्टूबर 2021, मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

टीवी रामायण के लंकेश अरविंद त्रिवेदी का निधन

मुंबई, (एजेंसी)। टीवी जगत के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभा चुके एटर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। उन्होंने 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। त्रिवेदी ने रामानन्द सागर की रामायण में रावण का किरदार निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया था। जानकारी के अनुसार, अरविंद त्रिवेदी का अंतिम संस्कार बुधवार सुबह मुंबई के दहानुकरवाड़ी श्मशान घाट में किया गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन बीती रात हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया।

नीट-एसएस एक्जाम 2021 पुराने पैटर्न पर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-सुपर स्पेशियलिटी 2021 पुराने पैटर्न के अनुसार आयोजित की जाएगी और नया पैटर्न अकादमिक सत्र 2022-23 से लागू किया जाएगा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्न की पीठ ने अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एश्वर्या भाटी की दलीलों को रिकॉर्ड में रखा और उन विद्यार्थियों की याचिकाओं का निपटान किया जिन्होंने इस वर्ष से नीट-सुपर स्पेशियलिटी के परीक्षा पैटर्न में बदलावों को लागू करने के केंद्र के पहले के फैसले को चुनौती दी थी।

महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र हाईकोर्ट जज नियुक्त

जबलपुर । प्रदेश के महाधिवता पुरुषेन्द्र कौरव मप्र हाईकोर्ट के नवागत जज नियुत किए गए है। इस संबंध में केंद्र के विधि एवं न्यायिक विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए है। जिसके बाद जल्द ही श्री कौरव हाईकोर्ट जज के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। उल्लेखनीय है कि श्री कौरव के नाम की सिफारिश सितंबर प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी। इसके बाद अब श्री कौरव का नाम केंद्र के विधि विभाग को भेजा गया, जहां से सारी औपचारिकताएं होने के बाद राष्ट्रपति की मुहर लगते ही सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

ग्वालियर स्टेशन पर 65 लाख का सोना पकड़ा

ग्वालियर । बुधवार को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर दो लोगों से जीआरपी ने 65 लाख रुपए के सोना के जेवर बरामद किए हैं। जीआरपी ने मामले की जानकारी आयकर व जीएसटी विभाग को दे दी है। जीआरपी डीएसपी शुभा श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति लगभग 1800 ग्राम सोना शतादी एसप्रेस में ग्वालियर के ज्वेलर्स से ललितपुर लेकर जा रहे हैं। टीम ने प्लेटफॉर्म क्रमांक एक पर दो व्यक्तियों को संदिग्ध हालत में देखा। जीआरपी जवानों ने जब बैग की तलाशी ली तो बैग में सोने के आभूषण मिले। पूछताछ में उनके पास कोई लिखित दस्तावेज नही मिला।

गंगा आरती की तरह ही होगी दिव्य सरयू आरती

नैनीताल, (एजेंसी)। गंगा आरती की तरह ही पर्यटक नगरी बागेश्वर में भी दिव्य व भव्य तरीके से सरयू आरती के आयोजन का निर्णय लिया गया है। प्रशासन इसके लिये तैयारियों में जुट गया है। मुयमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगले सप्ताह बागेश्वर दौरे पर इसका शुभारंभ कर सकते हैं। जिला प्रशासन, जूना अखाड़ा के महंतों व बागनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक में बुधवार को यह निर्णय लिया गया है। बैठक में यह भी तय किया गया कि पवित्र पावन सरयू नदी के किनारे बसे बागेश्वर शहर का पर्यटन के साथ साथ पौराणिक व धार्मिक महत्व भी है। बागनाथ मंदिर एक ऐतिहासिक धर्म स्थल है। यहां पर्यटकों के साथ ही तीर्थयात्री भी दर्शन के लिये आते हैं। इसलिये गंगा आरती की तर्ज पर दिव्य व भव्य सरयू आरती करने से पर्यटन व तीर्थाटन में बढ़ोतरी होगी।

लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत : संज्ञान

सीजेआई की अध्यक्षता में आज होगी सुनवाई

लखनऊ, एजेंसी।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में रविवार को हुए बवाल का सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्वतः संज्ञान लिया। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच करेगी। केस का टाइटल वायलेंस इन लखीमपुर खीरी लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ रखा गया है। जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली भी बेंच के सदस्य हैं। इससे पहले मंगलवार को हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। दो वकीलों ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दायर करने और उन्हें दंडित करने की मांग की थी।

याचिका में आग्रह किया गया है कि वह गृह मंत्रालय व पुलिस को मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दे। यह भी मांग की गई है कि हिंसा व उपद्रव की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए। सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निश्चित समय में जांच का आदेश भी दिया जा सकता है। **वहीं** लखीमपुर खीरी में हिंसा में जान गंवाने वाले बहराइच के किसान गुरविंदर सिंह का बुधवार सुबह अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले परिजन की मांग पर शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने बताया कि हिंसा में जान गंवाने वाले किसान गुरविंदर सिंह का उनके परिजनों की मांग पर मंगलवार-बुधवार की रात दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया है।

मंत्री की कुर्सी से खतरा टला: लखीमपुर खीरी किसान मौत मामले में फिलहाल केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी की कुर्सी से खतरा टल गया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक वे फिलहाल मंत्री बने रहेंगे। बुधवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ अजय मिश्रा की मुलाकात हुई थी, जहां उन्होंने सफाई दी थी।

पंजाब और छग की सरकारें देंगी 50-50 लाख रुपए

पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने उप्र के लखीमपुर खीरी जिले में हुई हिंसा में मारे गए किसानों के परिजन को 50-50 लाख की मदद राशि देने का ऐलान किया है। छग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एलान किया, शहीद हुए चार किसानों व एक पत्रकार के परिजन को 50-50 लाख रुपए देगी।

मृतक किसान लवप्रीत के परिवार से मिले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, बोले- बलिदान नहीं भूलेंगे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लखीमपुरी खीरी हिंसा में जान गंवाने वाले किसान लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार से मिलकर उनका दुख बांटा। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा। उन्होंने पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों से भी मुलाकात की, जिनकी हिंसा में मौत हो गई थी।राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि शहीद लवप्रीत के परिवार से मिलकर दुख बांटा लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा। लवप्रीत तुम्हारा बलिदान भूलेंगे नहीं । बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार रात पलिया तहसील पहुंचा और उसने रविवार को भड़की हिंसा में मारे गए चार किसानों में से एक किसान लवप्रीत सिंह के परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेता किसान के चौखड़ा फार्म स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिवार से बात की और उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी शामिल हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे ।राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हिंसा में जान गंवाने वाले पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों से भी मुलाकात की।

गांव में रहने वालों को मिलेगा अपनी संपत्ति का पूरा रिकार्ड, पीएम मोदी ने बताए स्वामित्व योजना के फायदे

भोपाल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 19 जिलों के 3000 गांवों में एक लाख 71 हजार हितग्राहियों को आनलाइन अधिकार अभिलेख का वितरण किया। प्रधानमंत्री ने सीहोर, हरदा और डिंडौरी जिले के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी किया। उन्होंने कहा, शुरुआती चरणों में स्वामित्व योजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान के कुछ गांवों में लागू किया गया था। इन राज्यों में गांवों में रहने वाले करीब 22 लाख परिवारों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुका है।

पीएम मोदी ने कहा, ड्रोन टेक्नोलाजी से किसानों को, मरीजों को, दूर-दराज के क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले इसके लिए हाल ही में अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। ड्रोन बड़ी संख्या में भारत में ही बने, इसमें भी भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए PLI स्कीम भी घोषित की गई है।

पीएम ने कहा, वो जमाना देश पीछे छोड़ आया है जब गरीब को एक-एक पैसे, एक-एक चीज के लिए सरकार के पास चक्कर लगाने पड़ते थे। अब गरीब के पास सरकार खुद चलकर आ रही है और गरीब को सशक्त कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजनाभर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नालाजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है।

मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से सात अक्टूबर तक चलाए जा रहे जनकल्याण और सुराज अभियान के तहत स्वामित्व योजना के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा जिले से शामिल होंगे। अन्य जिलों से हितग्राही और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। मालूम हो, स्वामित्व योजना को जिन नौ राज्यों में पायलट आधार पर लागू किया गया है, उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है।

डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। एक ई-ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू किया गया है जहां पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी उपलब्ध है। इस पोर्टल के जरिए किसानों को अपनी भूमि के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत आपको अपनी संपत्ति का सारा रिकार्ड आनलाइन प्राप्त करने में आसानी होगी और रजिस्ट्रेशन एवं सरकारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक क्लिक में अपनी संपत्ति का पेपर डाउनलोड कर सकेंगे।

राकांपा ने उठाए एनसीबी की छापेमारी पर सवाल

कार्रवाई फर्जी, नहीं मिली ड्रग्स

मुंबई, (एजेंसी)। क्रूज पोत पर छापेमारी को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ राकांपा ने बुधवार को आरोप लगाया कि मुंबई के तट के निकट एक क्रूज पोत पर दो अक्टूबर को की गई एनसीबी की छापेमारी 'फर्जी' थी और इस दौरान ड्रग्स नहीं मिला था।

एनसीबी टीम में था भाजपा कार्यकर्ता

एनसीपी प्रवक्ता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने छापेमारी के दौरान एनसीबी के दल के साथ दो लोगों की मौजूदगी पर भी सवाल उठाया। नवाब मलिक ने कुछ वीडियो और फोटो भी जारी किए। एनसीपी नेता ने कहा कि वीडियो में आर्यन खान के साथ चल रहा व्यक्ति एनसीबी का अधिकारी नहीं है और उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार वह कुआलालम्पुर निवासी एक निजी जासूस है। मलिक ने आरोप लगाया कि इसके अलावा एक अन्य वीडियो में दो व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट को ले जाते दिख रहे हैं और इनमें से एक बीजेपी का सदस्य है। उसका नाम मनीष भानुशाली है। मलिक ने कहा कि बीजेपी इस पूरे मामले में एनसीबी का इस्तेमाल लोगों, महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए कर रही है।

कैबिनेट ने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को 4,445 करोड़ रुपये की पीएम मित्र योजना को मंजूरी दी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर द्वारा बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों को लेकर जानकारी दी गई। कैबिनेट ने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 4,445 करोड़ रुपये की पीएम मित्र योजना को मंजूरी दी है। वहीं, इस दौरान ठाकुर ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया, कैबिनेट बैठक में दो विभागों को लेकर निर्णय हुए। वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नान गजेटेड कर्मचारियों को मिलता है। कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि इस वर्ष भी 78 दिन का बोनस रेलवे के नान गजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि बुधवार को कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान 4,445 करोड़ रुपये के मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। गोयल ने कहा, पीएम मित्र योजना लान्च होगी जो टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देगी। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें 5 वर्षों में 4445 करोड़ रुपये का व्यय होगा। 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क इसपर तैयार होंगे। मंत्रियों ने कहा कि इस कदम से रोजगार पैदा करने और क्षेत्र के लिए निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

पीयूष गोयल ने आगे बताया कि आरओएससीटीएल के लिए योजना 2019 में लॉन्च हुई थी जिसे 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में निर्यात को लेकर उत्साह है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, पीएम मित्र योजना से लगभग 7 लाख लोगों की सीधे तौर पर रोजगार मिले और 14 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिले, ऐसी हमारी कल्पना है। 10 राज्यों ने अभी तक इस योजना के लिए दिलचस्पी दिखाई है

इसके अलावा बोनस की घोषणा करते हुए ठाकुर ने कहा कि बोनस रेलवे कर्मचारियों को त्योहारी सीजन से पहले दिया जाता है जो आमतौर पर दशहरे से शुरू होता है। अनुराग ठाकुर ने कहा, बोनस कर्मचारियों को काम के प्रति प्रेरित करेगा और रेलवे के अंदर सुधार में भी मदद मिलेगी।

बेंजामिन और डेविड को संयुक्त नोबेल पुरस्कार

स्टॉकहोम ■ एजेंसी

जर्मनी के मैक्स-प्लैंक-इंस्टीट्यूट के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के लिए वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है।

रसायन विज्ञान में वर्ष 2021 संयुक्त रूप से मिला

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने बुधवार को यह घोषणा की। लिस्ट और मैकमिलन रसायन विज्ञान का नोबेल ऐसिममैट्रिक ऑर्गैनोकैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक, एक करोड़ स्वीडिश क्रोना (तकरीबन 8.20 करोड़ रुपए) की राशि दी जाती है। स्वीडिश क्रोना स्वीडन की मुद्रा है।

डेविड मैकमिलन

बेंजामिन लिस्ट

दुश्मन जैसा व्यवहार छोड़, विकास के मुद्दे पर साथ मिलकर करें काम : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली,एजेंसी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को सरकार और विपक्ष से कहा कि उन्हें विकास के मुद्दे पर साथ मिलकर काम करना चाहिए. उन्हें एक-दूसरे के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए. अगरतला में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में नायडू ने राजनीतिक दलों से एक-दूसरे का सम्मान करने की अपील की.

पूर्वोत्तर में विकास के बारे में नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार इस विशेष ध्यान दे रहा है और इसलिए यहां के फंड को डबल कर दिया गया है. अगर पूर्वोत्तर की एक दशक पहले से तुलना की जाए तो आज यहां काफी विकास हुआ है. उन्होंने कहा, 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के बिना भारत का विकास अधूरा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर विकास की शुरुआत करने वाले हैं और त्रिपुरा में यह दिखाई भी दे रहा है.

पूर्वोत्तर के विकास पर केंद्र सरकार का ध्यान'- वेंकैया नायडू ने कहा, 'भारत सरकार ने पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है और त्रिपुरा को इसका हिस्सा मिला है. राज्य ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी विकास किया है.' नायडू ने कहा कि त्रिपुरा में महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे को एक इंटरनेशन एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा. वहीं, उनाकोटि जिले में कैलासहर हवाई अड्डे को पुनर्जीवित करने और हेलीकॉप्टर सेवा के लिए नए रास्ते तलाशने के लिए पहल की जा रही है.

अभी कुछ दिन पहले ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश की नदियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत पर एक प्रभावशाली राष्ट्रीय अभियान चलाने का आह्वान करते हुए कहा कि इसे तात्कालिकता की भावना के साथ किया जाना चाहिए. नायडू ने कहा कि भारत में नदियां जीवनदायिनी शक्ति के लिए हमेशा से पूजनीय रही हैं. उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण ने देश के विभिन्न हिस्सों में नदियों और अन्य जलाशयों को दूषित किया है.

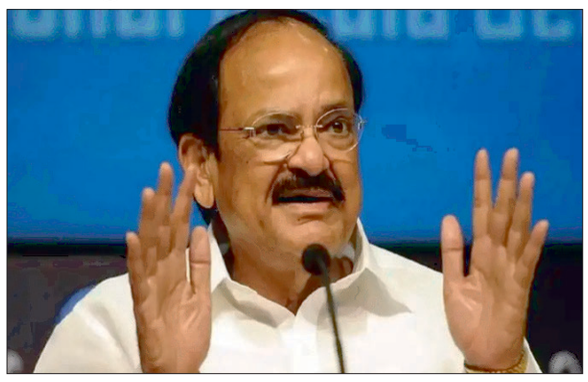

उपराष्ट्रपति ने कहा, 'अतीत में, हमारे गांव और शहर कई जलाशयों से युक्त हुआ करते थे. आधुनिकीकरण की चाह में मनुष्य ने लालच से प्रेरित होकर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को कई जगहों पर नष्ट कर दिया है, जिससे जलाशय गायब हो गए हैं या उनपर अतिक्रमण कर लिया गया है.' नायडू अपनी पूर्वोत्तर की यात्रा के तहत रविवार को यहां पहुंचे. उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे विरासत एवं सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करके की.

उपराष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, वह केंद्र के संग्रहालय भी गए और उन्होंने कॉफी टेबल पुस्तक 'फॉरएवर गुवाहाटी' का विमोचन भी किया. बाद में एक फेसबुक पोस्ट में नायडू ने असम और ब्रह्मपुत्र नदी की यात्रा के अपने अनुभव को अविस्मरणीय बताया. उन्होंने लिखा कि वह ब्रह्मपुत्र की प्राकृतिक सुंदरता से चकित हैं. इसका नज़ारा उन्होंने नदी के किनारे स्थित पार्क से देखा है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि लाखों लोगों को आजीविका देने वाली महान नदी इस क्षेत्र की संस्कृति और इतिहास का एक अभिन्न अंग है.

नदियों के महत्व और उनके कायाकल्प को रेखांकित करते हुए नायडू ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को जल संरक्षण के महत्व पर स्कूल पाठ्यक्रम में अध्याय शामिल करने चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों को छात्रों के लिए प्रकृति शिविर आयोजित करने चाहिए ताकि बच्चे, खासकर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे, प्रकृति की भव्यता को देख सकें. यात्रा के दौरान, नायडू ने केंद्र के कई हिस्सों जैसे कला दीर्घा, केंद्रीय कक्ष और 'माजुली कॉर्नर' को भी देखा. उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि विरासत परिसर में सिर्फ पैदल ही आया जा सकता है और इसमें गाड़ियों का लाना वर्जित है ताकि स्थान की शांति बनाई रखी जा सके.

रुझानों में शिवसेना चौथे नंबर पर, यानी जिस पार्टी का सीएम उस पार्टी की सीटें सबसे कम

नई दिल्ली,एजेंसी। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के नतीजों में अब तक सभी 6 जिला परिषदों की 85 सीटों और इनके 144 पंचायत समिति की सीटों के रुझान सामने आ गए हैं. इन रुझानों में शिवसेना चौथे नंबर पर चली गई है. यानी जिस पार्टी का सीएम, उनकी सीटें सबसे कम. शिवसेना सिर्फ पालघर में लीड करती हुई दिखाई दे रही है. इसके बाद नंदुरबार में भी बेहतर स्थिति में है. बाकी शिवसेना इन 6 जिला परिषदों में कहीं नहीं है.

जिलापरिषद के रुझानों में 85 में से 33 सीटों में बीजेपी आगे चल रही है और नंबर वन पर काबिज है. शिवसेना 12 सीटों पर आगे है और नंबर चार पर चल रही है. कांग्रेस और एनसीपी दोनों 17-17 सीटों पर आगे चल रहे हैं. पंचायत समिति की 144 सीटों की बात करें तो कांग्रेस 35 सीटों में आगे चल रही है और नंबर वन पर है. बीजेपी 33 सीटों में बढ़त बना कर नंबर दो पर है. शिवसेना 22 सीटों पर आगे चल रही है और एनसीपी 16 सीटों पर आगे चल रही है. यानी जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों की सीटों की मिला कर बात करें तो शिवसेना चौथे नंबर पर खिसकती हुई दिखाई दे रही है.

पालघर की बात करें तो जिला परिषद की 15 सीटों में शिवसेना 5 सीटों पर नंबर वन पर तो है, लेकिन यहां भी बीजेपी 5 सीटों में आगे होकर नंबर वन के खिताब के लिए शिवसेना को टक्कर दे रही है. अगर बीजेपी यहां शिवसेना से आगे निकल जाती है तो शिवसेना यहां भी दूसरे नंबर पर आ जाएगी. पालघर में पंचायत समिति की सीटों की बात करें तो शिवसेना 5 सीटों में आगे होकर नंबर वन पर चल रही है. यहां बीजेपी 3 सीटों पर आगे होकर नंबर 2 पर चल रही है. अन्य उम्मीदवार 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं. नंदुरबार में भी शिवसेना का प्रदर्शन अच्छा है लेकिन शिवसेना यहां नंबर वन पर नहीं चल रही है. जिला परिषद की सीटों में बीजेपी 4 सीटों में बढ़त बना कर नंबर वन पर बनी हुई है. शिवसेना और कांग्रेस में नंबर दो के लिए टक्कर है. दोनों 3-3 सीटों पर आगे चल रही हैं. लेकिन पंचायत समिति की सीटों में जरूर शिवसेना नंबर वन पर बनी हुई है. यहां शिवसेना 6 सीटों पर आगे है. कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है और बीजेपी 3 सीटों में आगे है.

नागालैंड में कांग्रेस की मांग, राज्य के बेहतरी के मुद्दे पर केंद्र और नागा विद्रोही एक दूसरे से करें बातचीत

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र और नागालैंड से संबंधित नगा राजनीतिक वार्ताकारों के बीच सहमत पदों को लागू करने की मांग की. इसने उत्तर पूर्वी राज्य में सरकार को मजबूत करने और एक कानून और एक कर प्रणाली को लागू करने की भी मांग की. नागालैंड एआईसीसी के प्रभारी सचिव अजय कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नेफियू रियो और नागालैंड विधानसभा की सर्वदलीय सरकार ने सही दिशा में कुछ नहीं करके राज्य के लोगों के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध किया है.

कुमार ने यहां पार्टी की एक बैठक में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में घोषणा की थी कि उसने नगा समस्या का समाधान कर लिया है. कुमार ने कहा, 'अगर ऐसा है तो हमारी मांग उन हिस्सों को लागू करने की है जो नागालैंड के लोगों के लिए लागू करने योग्य हैं.केंद्र ने कहा था कि समझौते में ऐसे मामले हैं जो नागालैंड राज्य और राज्य के दायरे से बाहर के लोगों से संबंधित हैं जो मामले राज्य से बाहर के मुद्दों से जुड़े थे, उनका समाधान नहीं किया गया. 'एक अलग संविधान, ध्वज और नागा स्वायत्त क्षेत्रों के एकीकरण जैसे मुद्दों पर समझौता नहीं किया जा सकता है, लेकिन केंद्र उस पर अमल क्यों नहीं कर रहा है जो बातचीत की गई है और राज्य से संबंधित है? नागालैंड के लोगों को क्यों भुगतना पड़ता है?

रियो सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट- नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार रियो सरकार को भारत में सबसे भ्रष्ट और सबसे बुरी तरह से शासित होने का संदिग्ध भेद है. उन्होंने यहां पार्टी की एक बैठक में कहा, 'फिलहाल नागालैंड का हर व्यक्ति कई तरह के कराधान और जबरन वसूली के कारण पीड़ित है, जो अनसुलझे नगा राजनीतिक मुद्दे के कारण होता है.' उन्होंने कहा कि कांग्रेस नागालैंड के लोगों के लिए लड़ेगी. 80 प्रतिशत से अधिक साक्षरता दर वाला राज्य बेहतर का हकदार है, लेकिन उसे देश की सबसे भ्रष्ट और अक्षम सरकार को भुगतना पड़ता है.

कुमार ने दावा किया कि नागालैंड का विविध धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से खतरे में है.

पुष्कर में दुर्गा पूजा महोत्सव से पहले एक कलाकार देवी दुर्गा की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा का बड़ा आरोप- मुझे गैर कानूनी रूप से रखा है कैद, 53 घंटे बाद भी नहीं बता पाई पुलिस

लखनऊ । लखीमपुर कांड के बाद से पीड़ित परिवारों से मिलने की जिद पर अड़ी कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने अपनी हिरासत को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बयान जारी कर आरोप लगाया है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से बलपूर्वक हिरासत में लिया गया। बिना किसी कानूनी आधार के उनके सांविधानिक अधिकारों का हनन करते हुए उन्हें सीतापुर पीएसी गेस्ट हाउस में कैद रखा गया है। वहीं, सीतापुर जिला प्रशासन ने सुबह आठ बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है।

प्रियंका वाड्रा सोमवार सुबह साढे चार बजे से सीतापुर पुलिस की हिरासत में हैं। बुधवार सुबह उन?हें हिरासत में लगभग 53 घंटे से ज?यादा हो गए हैं। गेट के बाहर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। रात में पीएससी गेटस हाउस के बाहर 15 मिनट के लिए लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से वहां हलचल

बढ़ गई। कार्यकर्ताओं को कुछ अप्रिय घटना का संदेह लगा था, लेकिन फिर स्थिति सामान?य हो गई। प्रियंका वाड्रा अभी भी लखीमपुर जाने के लिए अड़ी हुई हैं।

रविवार रात को ही लखनऊ आकर लखीमपुर के लिए रवाना हुईं कांग्रेस महासचिव को पुलिस-प्रशासन ने सीतापुर में हिरासत में ले लिया था। वह ऐलान कर चुकी हैं कि लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के परिवारों से मिले बिना वापस नहीं जाएंगी। मंगलवार दोपहर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी किया और फिर देर शाम प्रियंका ने अपना लिखित वक्तव्य जारी किया, जिसमें विस्तार से घटनाक्रम बताया है।

प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि चार अक्टूबर यानी सोमवार सुबह लगभग 4.30 बजे सीतापुर के सीओ पीयूष कुमार सिंह के मौखिक कथन पर उन्हें धारा 151 के तहत हिरासत में लिया गया। उस वक्त वह लखीमपुर जिले की सीमा से बीस किलोमीटर दूर थीं। सीतापुर में धारा 144 लागू नहीं हुई थी। वैसे भी वह दो कार्यकर्ता, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और निजी सचिव संदीप सिंह के साथ गाड़ी से जा रही थीं। चार लोगों के अलावा सुरक्षा दस्ता तक साथ नहीं था। तब भी हिरासत में लेकर दो महिला और दो पुरुष कांस्टेबल सीतापुर पीएसी परिसर ले आए।

कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी ने स्पष्ट कहा है कि पीएसी परिसर लाए जाने के बाद से अब तक पुलिस, प्रशासन या सरकार ने यह नहीं बताया कि उन्हें किन कारणों से और किन धाराओं में हिरासत में लिया गया है। हिरासत से संबंधित कोई नोटिस, आदेश या एफआइआर नहीं दिखाई गई। कांग्रेस नेता के मुताबिक, उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर एक कागज देखा है, जिसमें प्रशासन ने 11 लोगों को नामजद किया है, जिनमें से आठ लोग तो उनकी हिरासत के वक्त वहां मौजूद ही नहीं थे। प्रशासन ने उन दो लोगों को भी नामजद कर दिया, जो लखनऊ से सिर्फ कपड़े देने आए थे। प्रियंका ने कहा है कि उन्हें किसी मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी के सामने पेश नहीं किया गया। उनके वकील गेट पर खड़े हैं, लेकिन कानूनी सलाह लेने के लिए वकीलों से मिलने के अधिकार से वंचित रखा गया।

संक्षिप्त खबर

लखीमपुर खीरी हिंसा पर सियासी घमासान, राहुल के लखनऊ आने से पहले यूपी सरकार की दो टूक- माहौल बिगाड़ने नहीं देंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तो दंगल से पहले ही हिंसा हो गई, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच घटना के बाद से ही कुश्ती जारी है। यूपी के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले ही हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद विपक्षी दलों में पहले पीड़ित और घटनास्थल तक पहुंचने की होड़-दौड़ रविवार से ही शुरू हो गई और आज बुधवार को भी जारी है। पहले दिन रात में ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा दिल्ली से लखनऊ पहुंचकर लखीमपुर के लिए रवाना हो गईं, लेकिन सीतापुर में रोक कर हिरासत में ले ली गईं। लखीमपुर खीरी जाने के ऐलान के बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट से लौटा दिया गया। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव लखनऊ में सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरे, जो हिरासत में लेकर बाद में छोड़ दिए गए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी सीतापुर में हिरासत में ले लिए गए। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी लखीमपुर जाने की कोशिश में हैं। हालांकि सरकार ने उनकी तरफ से लखीमपुर खीरी जाने को लेकर मांगी गई अनुमति को खारिज कर दिया है। लखनऊ में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई है।

असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देगी योगी सरकार, दुर्घटना में मौत व स्थायी दिव्यांगता पर मिलेगी दो लाख रुपये बीमा राशि

लखनऊ । राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये तक का बीमा कवर मुहैया कराने का फैसला किया है। पंजीकृत मजदूरों व उनके परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्णय किया है। यह सुविधा उप्र असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक पंजीकृत हो चुके कामगारों और केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को मिलेगी। श्रम विभाग के प्रस्ताव पर फैसले की जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ ड्क्षसह ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी दुर्घटना में मृत्यु या शत-प्रतिशत दिव्यांगता पर दो लाख रुपये तक की बीमा राशि देने का प्राविधान है। वहीं 50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर एक लाख रुपये और 25 से 50 फीसद तक दिव्यांगता पर 50 हजार रुपये बीमा राशि दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर शुरू की गई मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों को साल में पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की निश्शुल्क सुविधा मिलेगी। उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड इस योजना का क्रियान्वयन स्टेट एजेंसी कंप्रीहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के माध्यम से कराएगा। इसके लिए बोर्ड और साचीज के बीच अनुबंध होगा। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की अनुमानित संख्या 4.5 करोड़ है। उप्र असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक 79,215 श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 24 लाख से ज्यादा श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं।

मांझी ने लालू यादव पर किया हमला- बोले-उपचुनाव से पहले मुझसे डर गए आरजेडी सुप्रीमो

पटना। बिहार की दो सीटों कुशेश्वरस्थान और तारापुर पर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सहमति के बाद पार्टी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर कांग्रेस को झटका दे दिया। राजद के इस स्टैंड को कांग्रेस ने गलत करार दिया और दोनों सीटों से अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। महागठबंधन की इस रस्साकशी के बीच हिन्दुस्तानी आवाम पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव पर सियासी हमला किया है। मांझी ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा है कि, लालू प्रसाद का ये डर अच्छा है। बिहार की दो विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सियासी बयानबाजी का दौर भी तेजी से शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में हिन्दुस्तानी आवामी मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर बड़ा हमला किया है। मांझी ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा है कि, जब लालू यादव सीएम थे, उस दौरान मैंने दशरथ मांझी जी को सम्मान देने के लिए कई बार कहा, लेकिन उनका जवाब ही अलग था। मांझी ने आगे लिखा है कि, लालू यादव का ये डर अच्छा है।

मंगलवार को आरजेडी के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को दिल्ली से लालू यादव ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया था। इस दौरान लालू यादव ने उपचुनाव को लेकर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि, जब मैं बिहार का सीएम था तो उस वक्त समाज में सबसे पिछड़ी कहे जानी वाली मुसहर जाति के लिए बहुत सारे काम किए थे। उपचुनाव को लेकर जातीय समीकर बताते हुए राजद सुप्रीमो ने कहा था कि, कुशेश्वरस्थान विधानसभा में यादव, अन्य जाति के साथ-साथ मुसहर जाति की भी अच्छी आबादी है। पार्टी ने गणेश भारती को इस वजह से टिकट दिया गया है, ताकि, इस इलाके के पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बिहार सीएम नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद, भाजपा पर लगाए आरोप

पटना । जन अधिकार पार्टी (जाप) सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें भाजपा और अस्पताल माफिया के दबाव में गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस में जाप के विलय को लेकर उन्होंने कहा कि राजद से कांग्रेस अलग होती है तो वे कांग्रेस को हर सहयोग करने को तैयार हैं। करीब पांच महीने जेल में रहने के बाद मंगलवार को पटना पहुंचे और प्रेस से बात कर रहे थे। जाप प्रमुख ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जेल में रहने के दौरान मेरे स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा गया। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाए कि एक विपक्षी पार्टी ईडी-सीबीआइ के डर से भाजपा से नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार से सवाल करती है। इसी वजह से ईडी-सीबीआइ इनकी संपत्ति जब्त नहीं करती। उन्होंने कहा, कांग्रेस अगर राजद से अलग होती है तो

यूपी के एक करोड़ स्टूडेंट्स को टैबलेट व स्मार्टफोन देगी यूपी सरकार, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

लखनऊ । युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित व स्वावलंबी बनाने के लिए योगी सरकार उन्हें मुफ्त में स्मार्ट फोन और टैबलेट देकर सशक्त व समर्थ बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरण योजना को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि युवाओं के डिजिटल सशक्तीकरण के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है। सरकार से यह सौगात पाने वाले युवाओं की संख्या 60 लाख से एक करोड़ तक हो सकती है। इस पर 3000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि टैबलेट व स्मार्टफोन स्नातक, परास्नातक, बीटेक, डिप्लोमा, पैरामेडिकल व नर्सिंग और कौशल विकास से जुड़े लाभार्थी युवा छात्रों को बांटे जाएंगे। इससे न केवल वे अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे, बल्कि उसके बाद विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी तथा स्वावलंबन की योजनाओं में भी इसका सदुपयोग कर नौकरी व रोजगार पा सकेंगे। कोरोना काल में आनलाइन शिक्षा, ट्यूटोरियल व कोचिंग अपरिहार्य हो गए हैं।

इस योजना का लाभ कौशल विकास विभाग के सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत व चिन्हित एजेंसियों के जरिये प्लंबर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक आदि सेवाएं देने वाले कुशल कारीगरों को भी दिया जाएगा। योजना के तहत प्रस्तावित लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय-समय पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से शामिल किया जा सकेगा। किस लाभार्थी वर्ग को टैबलेट देना है और किसे स्मार्टफोन, इसका निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे।टैबलेट व स्मार्ट फोन के वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण तथा चरणबद्ध क्रय के सम्बन्ध में भी निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा। भविष्य में आने

वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए योजना में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। छात्रों को टैबलेट व स्मार्टफोन के वितरण के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। चिन्हित शिक्षण संस्थानों की ओर से छात्रों की सूची समिति को उपलब्ध कराई जाएगी। टैबलेट व स्मार्टफोन जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदे जाएंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए औद्योगिक विकास विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की कोशिश है कि टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरण के लिए नवंबर के पहले हफ्ते तक छात्रों की सूची तैयार कर ली जाए।

गौरतलब है कि योगी सरकार ने युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन देकर उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट में 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में सत्ता में आने पर कॉलेज में दाखिला लेने वाले सभी युवाओं को मुफ्त लैपटाप देने का ऐलान किया था।

कानपुर के सर्किट हाउस में लगेगी अटल की प्रतिमा ? लोक भवन के बाद अब भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक और प्रतिमा लगाई जाएगी। यह प्रतिमा कानपुर नगर के सर्किट हाउस में लगाए जाने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रतिमा की स्थापना के लिए कुल लागत 37.35 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत प्रतिमा की स्थापना, प्लेटफार्म का निर्माण कार्य, स्टील की रेलिंग व अन्य कार्य सम्मिलित होंगे। प्रतिमा की आपूर्ति व स्थापना से जुड़े कार्यों के लिए प्रस्तावित 22.05 लाख रुपये में कुछ अन्य कार्यों को सम्मिलित करते हुए कुल 37.35 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा लगाई गई थी, जिसका अनावरण 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।

चित्रकूट पर्यटन व धार्मिक स्थल क्षेत्र को फ्री जोन घोषित ? प्रदेश सरकार ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र चित्रकूट में उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश की सीमाओं की बंदिशें खत्म करते हुए पर्यटन व धार्मिक स्थल क्षेत्र को फ्री जोन घोषित कर दिया है। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को दोनों प्रदेशों के बीच हुए करार के तहत वाहनों को एक दूसरे के यहां आने-जाने के लिए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित कुछ क्षेत्रों को वाहनों को कर से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामघाट को केंद्र मानते हुए दस किलोमीटर की परिधि में यह छूट होगी। इससे श्रद्धालु बगैर अतिरिक्त कर चुकाए बेरोकटोक आ-जा सकेंगे।

वाराणसी के दो मार्ग होंगे चौड़े, जाम से मिलेगी राहत ? वाराणसी के लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने व देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की राह आसान करने के लिए कैबिनेट ने दो प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्यों को मंजूरी दे दी है। इन निर्माण कार्य से शहर वासियों को रोजाना के जाम से बड़ी राहत मिल सकेगी।कैबिनेट ने वाराणसी में मोहनसराय दीनदयाल उपाध्याय नगर चकिया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-120) के चैनेज 0.000 से 10.200 के मध्य सर्विस लेन के साथ छह-लेन तथा चैनेज 10.200 से 11.180 के मध्य चार-लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (लंबाई 11.180 किलोमीटर) के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 412.53 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह मार्ग बीएचयू, डीएलडब्ल्यू, वाराणसी कैंट रेलवे व बस स्टेशन, सारनाथ, चंदौली, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। वाराणसी में वीआइपी मूवमेंट, देश-विदेश से पर्यटकों व श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार रहता है। इस मार्ग पर यातायात घनत्व अत्यधिक होने के कारण अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा वाराणसी-भदोही-गोपीगंज मार्ग के चैनेज 4.310 से 12.910 तक चार-लेन चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (लंबाई 8.600 किलोमीटर) कार्य के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 269.10 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वाराणसी-भदोही-गोपीगंज मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-87) के चैनेज 0.00 से 4.310 तक का भाग सघन शहरी क्षेत्र है। मार्ग का चैनेज 4.310 मोहनसराय दीनदयाल उपाध्याय नगर चकिया मार्ग से चांदपुर चौराहा (कलेक्ट्री फार्म) पर स्थित है। मार्ग के चैनेज 4.310 से 12.910 तक का भाग चांदपुर चौराहा (कलेक्ट्री फार्म) से वाराणसी रिंग रोड फेज-दो को जोड़ता है। मार्ग का यह भाग रिंग रोड व विश्वविख्यात कालीन निर्माण केंद्र भदोही से वाराणसी शहर का प्रवेश मार्ग है।

गांठ तो हो गई पर चलता रहेगा राजद और कांग्रेस का गठबंधन, भाजपा-जदयू के तानों पर नहीं देंगे ध्यान

पटना। बिहार में विपक्षी दलों के सबसे बड़े गठबंधन में गांठ भले पड़ गई है, लेकिन बंधन अभी टूटा नहीं है। विधानसभा की दो सीटों तारापुर और कुशेश्वरस्थान के लिए होने वाले उपचुनाव में राजद और कांग्रेस ने भले ही एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन दोनों ही दल अभी गठबंधन टूटने की बात नहीं कह रहे हैं। राजद के नेताओं ने औकात और हैसियत तक बात पहुंचाई, भाजपा और जदयू के नेता तंज कसते रहें, लेकिन कांग्रेस अभी अपने सहयोगी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। इसका पता इस बात से चलता है कि पप्पू यादव की शर्त पर कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चर्चाएं हैं कि कांग्रेस ने पप्पू यादव को तारापुर सीट से चुनाव लड़ने का आफर दिया था। इसके बाद पप्पू ने कहा कि वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं बशर्ते पार्टी राजद से अपना नाता तोड़ ले।

पप्पू यादव की शर्त पर राजी होने की बजाय कांग्रेस ने तारापुर सीट से दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। इससे लगता है कि कांग्रेस ने भले ही

अपनी नाक बचाने के लिए विधानसभा की दोनों सीटों पर राजद के खिलाफ अपना उम्मीदवार दे दिया, लेकिन दोनों दलों का साथ अभी बना रहेगा। तेजस्वी यादव ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। दोनों सीटों पर राजद-कांग्रेस के आमने-सामने होने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि यह तो उप चुनाव है। चर्चाएं हैं कि दोनों दलों के रिश्तों में यह गांठ कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री की वजह से हुई है।

इधर, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि बिहार में होने वाले किसी भी चुनाव से पहले कांग्रेस के कुछ नेता राजद को आंख दिखाने की नौटंकी करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में अपने कहे को पूरा करने की रत्ती भर भी हिम्मत नहीं है। इस तरह के बयानों से इनके नेता कार्यकर्ताओं के सामने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी है कि अगर वह राजद से नहीं डरते हैं तो महागठबंधन से अलग हटने का ऐलान करें। राजीव रंजन ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस का पूरा अस्तित्व राजद पर टिका हुआ है। इनके पास न तो जनाधार बचा है और नहीं जनाधार वाले नेता, दूसरी तरफ राजद जब चाहे इनकी पार्टी के इतने टुकड़े कर दे कि कोई पंजे का झंडा उठाने वाला भी नहीं बचेगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि राजद का इतिहास और चरित्र गठबंधन के साथियों को धोखा देना रहा है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो भाजपा के सहयोग से बने, जिसके बदले में लालू ने भाजपा को धोखा दिया। झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी झामुमो को धोखा दिया। वीआइपी प्रमुख मुकेश साहनी की पार्टी को धोखा दिया और अब कांग्रेस को औकात पर ला कर खड़ा कर दिया है।

आखिरकार चारों किसानों का हो गया अंतिम संस्कार, तड़के हुआ चौथे का पोस्टमार्टम

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा के दौरान मृत चार किसानों में तीन का मंगलवार को अंतिम संस्कार दिया गया लेकिन बहराइच का मोहरनिया निवासी परिवार दोबारा पोस्टमार्टम पर अड़ा गया। मोहरनिया के मृत किसान गुरुविंदर सिंह के परिवारजन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत करार देते हुए मृतक को गोली मारने की बात कही। देर शाम राकेश टिकैत मृत किसान गुरुविंदर सिंह के घर पहुंचे। स्वजन मृतक का दोबारा दिल्ली में पोस्टमार्टम कराने की जिद कर रहे थे। आखिरकार तड़के चार बजे दोबारा पोस्टमार्टम के बाद मोहर्नियां में मृत किसान का अंतिम संस्कार करा दिया गया।

मृतक किसान गुरुविंदर के दोबारा पोस्टमार्टम की मांग पर लखनऊ से चार सदस्यीय चिकित्सकों की टीम हेलीकाप्टर से बहराइच पहुंची, लेकिन किसान नेता व परिवारजन शव दिल्ली ले जाने की मांग कर रहे हैं। परिवार ने कहा कि गोली मारी गई। गुरुविंदर के पिता सुखविंदर सिंह का आरोप था कि बेटे की हत्या गोली मार कर की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। गोरखपुर के एडीजी जोन अखिल कुमार ने परिवारजन से बात कर दोबारा चिकित्सकों की टीम से पोस्टमार्टम कराने का भरोसा दिया, लेकिन मौके पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत व परिवारजन शव को एयर लिफ्ट कराकर दिल्ली में दोबारा पोस्टमार्टम की बात पर अड़े रहे। टिकैत ने कहा कि संयुक्त मोर्चा एवं पीड़ित परिवार की मांग के अनुरूप फैसला होना चाहिए। आखिरकार अधिकारी देर रात मृतक के परिवारजन को समझाने में सफल रहे। परिवारजन की मांग के मद?देनजर बुधवार को भोर में जिला मुख्यालय पर चिकित्सकों के विशेष दल ने पोस्टमाटम किया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच शव को मोहर्निया गांव ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। लखीमपुर खीरी में चौखड़ा निवासी लवप्रीत और धौरहरा नक्षत्र सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस एवं प्रशासन के उच्चाधिकारियों व किसान नेताओं की उपस्थिति में दाह संस्कार हुआ। पहले परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत होने का आरोप लगाकर दाह संस्कार करने से मना कर दिया था। इसके बाद किसान वहां पर जमा होने लगे थे। किसान नेता राकेश टिकैत भी चौखड़ा फार्म पहुंच गए थे। काफी देर तक जिद्दोजहद चलने के बाद स्वजन व किसान लवप्रीत के शव को लेकर मझगई आ गए और वहां पर मार्ग जाम कर दिया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और विश्वास दिलाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। बाद में परिवारजन व किसान नेता दाह संस्कार करने पर राजी हो गए। जबकि नानपारा कोतवाली के बंजारन टाड़ा निवासी दलजीत सिंह का मंगलवार को शव आने के बाद प्रशासन के समझाने पर अंतिम संस्कार देर शाम हो गया। टिकैत पहुंचे मृतक पत्रकार रमन कश्यप के घर ? मंगलवार को राकेश टिकैत निघासन में मृतक पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे और मृतक के परिवार से मिलकर ढांढ़स बंधाते हुए कहा कि हमारी संवेदना आपके साथ है।

यूपी पुलिस ने दुर्गा पूजा व दशहरा को लेकर जारी की गाइडलाइन, पीएसी व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल रहेगा मुस्तैद

लखनऊ । लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी शांति-व्यवस्था की चुनौती बढ़ती जा रही है। लखनऊ और सीतापुर में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच पुलिस प्रशासन की निगाहें अब कई अन्य संवेदनशील जिलों पर टिकी हैं। खुफिया तंत्र को सक्रिय किए जाने के साथ ही कई जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने के दिश-निर्देश दिए गए हैं। खासकर सात अक्टूबर से शुरू हो रही नवरात्रि और 15 अक्टूबर को दशहरा की शांति-व्यवस्था किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगी। यही वजह है कि इस बाद दुर्गापूजा, रामनवमी व दशहरा की सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर कड़े बंदोबस्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान 183 कंपनी पीएसी व पांच कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती होगी। इसे लेकर डीजीपी मुख्यालय स्तर से कई कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा, राम नवमी व दशहरा की सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर कडे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। कहीं भी अफवाह फैलाने अथवा गड़बड़ी करने वालों से पुलिस पूरी सख्ती से निपटेगी। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस और पीएसी मुस्तैद की जाएगी। इस दौरान पांच कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी अलग-अलग स्थानों पर तैनात रहेगा। इंटरनेट मीडिया की निगरानी के कड़े निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर में कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की हत्या के बाद पुलिस की कार्यशैली कठघरे में थी। मनीष हत्याकांड में पुलिस कार्रवाई के कदम बढ़ाए जाने के दावे कर स्थिति को कुछ हद तक संभाल सकी थी। अब लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा ने पुलिस की मुश्किलें अचानक काफी बढ़ा दी हैं। ऐसे में शरारती तत्वों व इंटरनेट मीडिया के जरिए भ्रामक सूचनाओं का प्रसार करने वालों पर भी कड़ी निगाह रखनी होगी। सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर व्यापक रणनीति बनाई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती हापुड़, कानपुर कमिश्नरेट, लखनऊ कमिश्नरेट, गोरखपर व मऊ में तैनात रहेंगी।

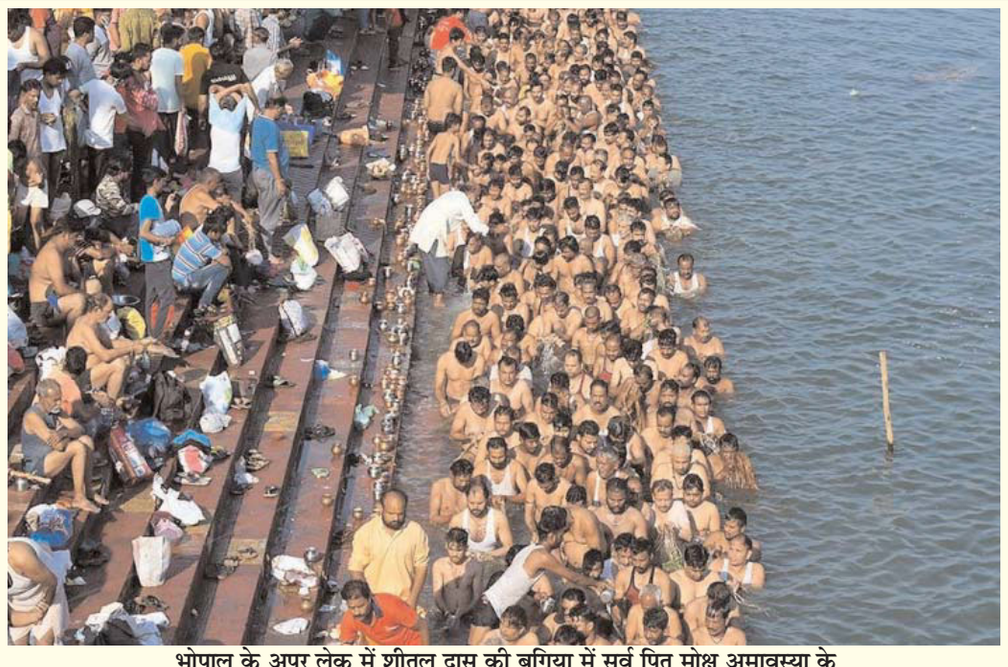

भोपाल के अपर लेक में शीतल दास की बगिया में सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त तर्पण करते हुए।

हत्यारों को बचा रही है उप्र सरकार : केजरीवाल

लखीमपुर खीरी घटना पर केजरीवाल ने मोदी से की किसानों को न्याय दिलाने की मांग

नई दिल्ली, प्रफुल्ल राय(शिवालिक)।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रधानमंत्री से सभी देशवासियों की तरफ से उप्र के लखीमपुर खीरी घटना मामले में किसानों को न्याय दिलाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी सरकार हत्यारों को बचा रही है। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या मजबूरी है? हत्यारों को क्यों बचाया जा रहा है? सरेआम कोई भीड़ के सामने किसानों को रौंदते हुए निकल गया और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने घुटने टेक कर उसे बचाने में लग गया है। उस गाड़ी ने वहां मौजूद सिर्फ कुछ किसानों को ही नहीं कुचला है, बल्कि इस देश के सभी किसानों को कुचला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार और पूरे सिस्टम को ही कुचल दिया है। किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर बैठे हैं। अब तक 600 से अधिक किसानों की जान जा चुकी है और अब उन्हें कुचल कर मारा जा रहा है। आखिर किसानों से इतनी नफरत क्यों। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हर देशवासी टीवी और सोशल मीडिया पर देख रहा है कि एक गाड़ी आई और किसानों को रौंद कर चली गई। इसके बाद, जिस तरह से पूरी सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है, इससे क्या

- **आखिर किसानों से इतनी नफरत क्यों है : केजरीवाल**
- **पूरे सिस्टम पर हत्यारे के सामने घुटने टेकने का लगाया आरोप**

संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो, तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो। उस गाड़ी ने वहां मौजूद सिर्फ कुछ किसानों को ही नहीं कुचला है, बल्कि इस देश के सभी किसानों को कुचला है, इस देश के गरीबों को कुचला है। ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार और पूरे सिस्टम को ही कुचल दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, आज एक तरफ सरकार 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रही है और दूसरी तरफ, जब विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं, तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। यह कौन सी आजादी का जश्न है, ऐसे तो अंग्रेज करते थे। क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए संघर्ष किया था और कुर्बानियां दी थी। आखिर वहां ऐसा क्या है, जो छुपाया जा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई कि वहां न किसी पत्रकार को पहुंचने दिया जा रहा है, न किसानों को पहुंचने दिया जा रहा है और न किसी विपक्ष के नेता को पहुंचने दिया जा रहा है। आज पूरा भारत यह जानना चाहता है कि लखीमपुर में आखिर हुआ क्या था? किसने गाड़ी चढ़ाई और क्यों चढ़ाई। सच्चाई जानना तो देश के लोगों का अधिकार है न।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम के संज्ञान में लाते हुए कहा कि पिछले एक साल से किसान बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। अब तक 600 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है और आज किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उन्हें कुचल कर मार डाला जाता है। आखिर किसानों से इतनी नफरत क्यों है।

हत्यारोपियों को तुरंत किया जाए गिरफ्तार : केजरीवाल

मुख्यमंत्री ने पीएम से मांग करते हुए कहा कि सारा देश चाहता है कि हत्यारोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और संबंधित मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड मामले में किसानों को न्याय दिलाने की मांग की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ, आज पूरा देश उसकी चर्चा कर रहा है। हर जगह यही बात हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम उन निर्दोष किसानों के हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने देशवासियों की तरफ से सवाल रखते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड मामले में अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आखिर क्या मजबूरी है। उन्हें क्यों बचाया जा रहा है। हत्यारों ने दिन-दहाड़े, इतनी भीड़ के सामने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और फिर भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्हें क्यों बचाया जा रहा है। सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नत मस्तक होकर और घुटने टेक कर, उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हम हिंदी फिल्मों में देखा करते थे।

दिल्ली के इन 6 सरकारी अस्पतालों में अब नही होगी आक्सीजन की किल्लत, पीएसएम प्लांट का हुआ उद्घाटन

नई दिल्ली । दूसरी लहर के दौरान आक्सीजन की भारी किल्लत से जूझने के बाद बुधवार को संभावित तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र के छह बड़े सरकारी अस्पतालों में क्षेत्रीय विधायकों द्वारा पीएसए (प्रेशर स्विंग एडसरप्शन) प्लांट का उद्घाटन किया गया। इसमें हरि नगर स्थित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, जाफरपुरकलां स्थित रावतुला राम अस्पताल, डाबड़ी स्थित दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, मोती नगर स्थित आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल, द्वारका सेक्टर-10 स्थित इंदिरा गांधी अतिविशिष्ट अस्पताल व जनकपुरी स्थित अतिविशिष्ट अस्पताल शामिल है। हालांकि संभावित तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए यह तैयारी अभी भी आधी अधूरी ही नजर आती है। जानकारों के मुताबिक सभी अस्पतालों में अभी तक लिक्विड आक्सीजन टैंक नहीं लगे हैं और कई अस्पतालों में तो केंद्रीय गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। बिना लिक्विड आक्सीजन टैंक के पीएसए प्लांट का इस्तेमाल संभव नहीं है और यही कारण है कि अभी भी अस्पताल आक्सीजन के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं बने हैं। साथ ही आक्सीजन सिलेंडर से भी अस्पतालों की निर्भरता अभी भी खत्म नहीं हुई है।

दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय व इंदिरा गांधी अतिविशिष्ट अस्पताल में पीएसए प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक विनय मिश्रा ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में आक्सीजन की भारी किल्लत की समस्या सामने आई थी। जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। भविष्य में ऐसा दोबारा न हो इसके लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी अस्पतालों को सशक्त बनाने की दिशा में यह अहम कदम है। तीसरी लहर के दौरान अस्पतालों को अब आक्सीजन की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा।

अस्पताल प्रशासन की मानें तो प्राथमिक स्तर पर दादा देव अस्पताल के आपातकाल विभाग में 35 बेड को पाइपलाइन के माध्यम से पीएसए प्लांट से जोड़ा गया है। जहां तक सभी बेड की बात नई इमारत का निर्माण कार्य प्रगति पर है जैसे ही कार्य पूरा होगा अस्पताल में केंद्रीय गैस पाइपलाइन के साथ अपना लिक्विड आक्सीजन टैंक भी होगा। जिसके बाद अस्पताल आक्सीजन के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होगा।

वहीं जनकपुरी स्थित अतिविशिष्ट अस्पताल में विधायक राजेश ऋषि ने पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया और उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों का कार्य सराहनीय रहा और यदि संभावित तीसरी लहर आती है तो उसके लिए भी अस्पताल पूर्ण रूप से तैयार है। आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल में शिव चरण गोयल पहुंचे और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में राजकुमार ढिल्लो ने पीएसए प्लांट की शुरुआत की।

संक्षिप्त खबर

केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल ने सड़क का किया लोकार्पण

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुजर, सांसद रमेश बिधूड़ी और दक्षिणी दिल्ली के महापौर मुकेश सुर्यान ने बुधवार को आया नगर वार्ड में चौधरी जगत सिंह मार्ग का लोकार्पण किया। समारोह की अध्यक्षता स्थानीय पार्षद वेदपाल ने की। इस अवसर पर महापौर ने बताया कि दक्षिणी निगम अपने अधिकारी क्षेत्र में आने वाले मार्गों, स्थानों, व पार्कों का नामकरण क्षेत्र के विभिन्न समाजसेवी व लोकप्रिय नागरिकों के नाम पर कर रहा है ताकि लोग उन्हें और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद रख सके।

पूर्वी निगम ने मलबे के निपटान के लिए बनाई योजना

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने इसको नियंत्रित करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इस संबंध में पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के सुरक्षित एवं पर्यावरण हितैषी निपटान के संबंध निगमायुक्त, विकास आनंद द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सी एंड डी कचरे सहित प्रदूषण पैदा करने वाले कारकों को कम करने की तत्काल आवश्यकता है। इस आदेश में कहा गया है कि भवनों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण करने वाले सभी मालिक एवं बिल्डर इस तरह के निर्माण पुनर्निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले निर्माण और विध्वंस कचरे का शास्त्री पार्क में सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र में अनिवार्य रूप से निपटान करेंगे और और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी और स्वीकृत भवन योजना को भी रद्द किया जा सकता है। इस संबंध में पूर्वी निगम के सभी कनिष्ठ अभियंता भवन के लिए आदेश किये गये हैं कि वे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में भवनों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण करने वाले मालिकों तथा बिल्डरों द्वारा सी एंड डी अपशिष्ट का अनिवार्य निपटान सुनिश्चित करेंगे और अपने दौर के दौरान उन्हें इस बारे में शिक्षित करेंगे।

दक्षिणी निगम की तदर्थ समिति के पद के लिए नामांकन

नई दिल्ली। दक्षिणी निगम की तदर्थ लाभकारी परियोजना समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए राधिका अबरोल व अनिता तंवर ने नामांकन भरा। उन्होंने अपना नामंकन पत्र निगम सचिव को प्रस्तुत किया। तदर्थ लाभकारी परियोजना समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन पहली बैठक 12 अक्टूबर को होगा।

स्किल इंडिया के प्रशिक्षु नियुक्त

नई दिल्ली। युवाओं के लिए कौशल विकास के अभियान स्किल इंडिया के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त तकरीबन 52 हजार प्रशिक्षुओं को विभिन्न संस्थानों ने नियुक्त किया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से आज देश भर में 660 से अधिक स्थानों पर एक दिवसीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया गया। बताया जाता है कि इसके जरिए 51 हजार 991 प्रशिक्षुओं को काम पर रखा गया था। 30 से अधिक क्षेत्रों बिजली, खुदरा, दूरसंचार, आईटी, आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर वाहन आदि है। इसके अतिरिक्त इच्छुक युवाओं को वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और अन्य पदों सहित 500 से अधिक व्यवसायों से जुड़ने और संभावनाओं का चयन करने का अवसर मिला।

यमुना की सफाई के बिना स्वच्छ दिल्ली की कल्पना असंभव : आदेश गुप्ता

नई दिल्ली (संवाददाता)। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू किए गए सेवा और समर्पण अभियान के तहत एक विशेष अभियान चलाकर यमुना की सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया। 71 विभिन्न जगहों पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी गणमान्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और यमुना नदी की सफाई की और आगे भी सफाई अभियान निरन्तर चलता रहे, इसका वादा किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आईटीओ स्थित छठ घाट पर यमुना की सफाई के दौरान कहा कि यमुना की सफाई के बिना स्वच्छ दिल्ली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यमुना के अंदर जो प्रदूषण है, वो कैसे समाप्त होता है यह दिल्ली सरकार की जवाबदेही है लेकिन दिल्ली के नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम यमुना की सफाई में श्रमदान दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुरू किया गया सेवा और समर्पण अभियान के तहत यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में छठ का त्योहार हम साफ सफाई के साथ और स्वच्छ वातावरण के साथ मना सके।

आदेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा छठ पूजा पर रोक लगाने का फैसला बिल्कुल गलत है। आज दिल्ली में बाजार पूरी तरह खुल चुका है और साथ ही कही पर भी आने जाने पर रोक नहीं है तो ऐसे में छठ पूजा पर रोक लगाने का क्या मतलब है। सफाई अभियान में गुप्ता के साथ कार्यक्रम के संयोजक और प्रदेश भाजपा महामंत्री कुलजीत सिंह चहल और प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल सहित कई कर्यकर्ता मौजूद थे।

गूगल पर आरटीओ के कई फर्जी वेबसाइट

हजारों लोगों से लाखों की ठगी का खुलासा

(एजेंसी)

नई दिल्ली। अगर पर गूगल पर सर्च करके ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी समेत अन्य सुविधाओं के लिए सरकार की ऑनलाइन ई-परिवहन वेबसाइट का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि इस वेबसाइट से मिलती-जुलती कई फर्जी वेबसाइट भी ऑनलाइन मौजूद हैं, जहां लोगों के साथ ठगी की वारदातों को धड़ल्ले से अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने ऐसे ही कुछ फर्जी वेबसाइट का सनसनीखेज खुलासा करते हुए, एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है, जिसने इन फर्जी वेबसाइट की मदद से करीब 3300 से भी ज्यादा लोगों से 70 लाख की ठगी की है। डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने आरोपी की पहचान 30 वर्षीय कपिल त्यागी के तौर पर की है, जो गाजियाबाद का रहने वाला है। आरोपी को उसके गाजियाबाद स्थित घर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 10 चेकबुक, 15 सिम, 4 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 2 पेनड्राइव, 2 हार्डड्राइव और 15 डेबिट-क्रेडिट कार्ड बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के बैंक खाते में मौजूद ठगी के 8.34 लाख रुपए भी फ्रीज कर दिए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस फर्जीवाड़े को लेकर परिवाहन मंत्रालय, भारत सरकार के एमवीएल एंड आईटी के निदेशक पीयूष जैन ने स्पेशल सेल को शिकायत दी थी। जिसके आधार पर पुलिस ने गत 2 अक्टूबर को मामले में आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत केस दर्ज कर एसीपी रमन लांबा की निगरानी में एसआई करमबीर, एसआई सोनम जोशी, हेड कांस्टेबल नवीन और कांस्टेबल दीपक की टीम ने छानबीन शुरू की थी।

भारत सरकार के परिवाहन मंत्रालय का फर्जी वेबसाइट चलाने वाला एक शातिर गिरफ्तार

बैंक खातों से आरोपी तक पहुंची पुलिस

पुलिस की टीम ने जांच के दौरान सभी फर्जी वेबसाइट के बारे में जानकारी जुटाई। इन वेबलाइट पर होने वाली ऑनलाइन पेमेंट को खंगाला। साथ पीड़ितों के बैंक खातों की भी जांच की। जांच में खुलासा हुआ कि सारी रकम ग्लोबल इंडिया सर्विसेज नामक कम्पनी के बचत खाते में जा रही है। आरोपी गूगल एड्स पर फर्जी वेबसाइट को सर्च इंजन में सबसे ऊपर दिखाया जाता था। ताकि लोग आसानी से उसपर ठगी का शिकार बनाए जा सके। जांच के बाद पुलिस टीम ने डिजिटल फुटप्रिंट के जरिए आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गाजियाबाद में स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पहले फर्जी कॉल सेंटर में काम कर चुका है, जहां उसने लोगों से ऑनलाइन ठगी करने की तकनीक सीखी थी।

दिल्ली में 29 अक्टूबर तक चलेगा धूल विरोधी अभियान: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

नई दिल्ली,(रविशंकर तिवारी)। दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली में 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक एंटी डस्ट अभियान चलाया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर कल से निर्माण संबंधी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है। इसके संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी किया जा चुका है। एंटी डस्ट अभियान के तहत 31 टीमों का गठन किया गया है। जिसमें डीपीसीसी की 17 और ग्रीन मार्शल की 14 टीमें शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक 10 हजार से 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। सीएंडडी वेस्ट के सेल्फ ऑडिट और प्रबंधन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विंटर एक्शन

प्लान की घोषणा की है। जिसके आधार पर पर्यावरण विभाग ने इसे जमीन पर लागू करने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। हमने कल ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप को लांच किया था। इसके बाद आज डीपीसीसी के इंजीनियर और ग्रीन वॉर रूम से जुड़े ग्रीन मार्शल के साथ संयुक्त बैठक की है। जिसमें फैसला लिया है कि दिल्ली के अंदर सबसे पहले धूल प्रदूषण को कम करने पर काम करेंगे। दिल्ली में 7 से 29 अक्टूबर तक एंटी डस्ट अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली के अंदर पिछले साल भी एंटी डस्ट अभियान चलाया था। उसका असर धूल प्रदूषण को कम करने में दिखा था।

कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण के यह तय किए गए नियम

गोपाल राय ने कहा कि निर्माण संबंधी नियमों को लेकर पहले अपील की जा चुकी है। कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण के लिए यह तय नियम तय किए गए हैं। सभी निर्माण साइटों पर निर्माण स्थल के चारों तरफ टीन की ऊंची दीवार खड़ी करना जरूरी है। बीस हजार वर्ग मीटर से अगर ऊपर का कार्य है तो उसके निर्माण और ध्वस्तीकरण में एंटी स्मॉग गन लगाना जरूरी है। निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य के लिए त्रिपाल या नेट से ढकना जरूरी है। निर्माण स्थल पर निर्माण सामग्री को लाने ले जाने वाले वाहनों की सफाई करना जरूरी है। निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को पूरी तरह से ढकना जरूरी है। निर्माण सामग्री और ध्वस्तीकरण का मलबा चिन्हित जगह पर ही डालना जरूरी है।

एप्लाइड मैथमेटिक्स को गणित के बराबर दर्जा देगा डीयू, व्यवहारिक गणित पढ़ने वालों को मिलेगी राहत

नई दिल्ली । जिन छात्रों ने 12वीं में एप्लाइड मैथमेटिक्स यानी व्यवहारिक गणित पढ़ा है, उनके लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली विश्वविद्यालय व्यवहारिक गणित पाठ्यक्रम को गणित के बराबर दर्जा देगा। बेस्ट आफ फोर और बेस्ट आफ थ्री के कैलकुलेशन के दौरान व्यवहारिक गणित को गणित के समान ही अंक दिए जाएंगे। डीयू ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ बीकाम आनर्स और बीकाम प्रोग्राम में दाखिले के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बीए आनर्स में दाखिले के दौरान व्यवहारिक गणित को गणित के बराबर दर्जा नहीं दिया जाएगा। डीयू ने इस बाबत एक सर्कुलर भी जारी किया है।

डीयू ने स्पष्ट किया है कि आवेदन फार्म भरने के बाद कोई भी छात्र किसी भी परिस्थिति में अपनी श्रेणी नहीं बदल पाएगा। हालांकि डीयू के इस नियम पर शिक्षक संगठनों ने ऐतराज जताया है। दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) अध्यक्ष डा. हंसराज सुमन ने कहा है कि इससे आरक्षित वर्ग के छात्र सामान्य श्रेणी के तहत दाखिला नहीं ले पाएंगे। डीटीए ने कार्यवाहक कुलपति प्रो. पीसी जोशी को पत्र लिखकर इस नियम को हटाने की गुजारिश की है।

डीटीए ने कहा कि दिशानिर्देश में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में श्रेणी परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यह भारत के संविधान में प्रदत्त शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधानों के विपरीत है।

संबंधित पाठ्यक्रम नहीं हुए तो कटेंगे 2.5 फीसद- दिल्ली विवि ने बेस्ट फोर कैलकुलेट करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिनमें कहा गया है कि एक भाषा पाठ्यक्रम अनिवार्य है। यदि दो भाषा पाठ्यक्रम है तो एक को कोर जबकि दूसरे को इलेक्टिव पाठ्यक्रम या फिर दोनों को इलेक्टिव माना जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी में बीए आनर्स के लिए 12वीं में उपर्युक्त विषय पढ़ना अनिवार्य है। अन्य भाषा में बीए आनर्स करने के लिए छात्र को 12वीं में संबंधित भाषा पढ़ना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो बेस्ट फोर कैलकुलेट करते समय 5 फीसद अंक काटे जाएंगे। अन्य आनर्स प्रोग्राम जैसे इतिहास, भूगोल और मनोविज्ञान आदि में दाखिले के लिए बेस्ट फोर कैलकुलेट करते समय भी 2.5 फीसद अंक काटे जाएंगे यदि छात्र ने संबंधित विषय 12वीं में नहीं पढ़े हैं तो।

कैसे हीरो बनने की चाहत में विलेन बन गए किसान संगठन, लाखों लोगों की जिंदगी बना दी नर्क

नई दिल्ली/गाजियाबाद । तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली-एनसीआर के चारों बार्डर (सिंघु, टीकरी, शाहजहांपुर और गाजीपुर) पर जारी किसानों का प्रदर्शन बिल्कुल नीरस पड़ चुका है। आंदोलन की शुरुआत कर हीरो बनन के चक्कर में कुछ इस तरह की हरकतें होती रहीं कि किसान नेता हीरो के बजाय विलेन बनते गए। वहीं, खासकर 3 अक्टूबर से सिंघु, टीकरी, शाहजहांपुर और गाजीपुर बार्डर पर प्रदर्शन कर रहे तमाम दिग्गज किसान नेता लखीपुरखीरी (उत्तर प्रदेश) की ओर कूच कर गए हैं या फिर कूच करने वाले हैं। दरअसल, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन का मिजाज ही पूरी तरह से बदल गया है।

स्थिति यह है कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों की वापसी की चर्चा ही नहीं हो रही, बल्कि मुद्दा अब लखीमपुर खीरी हिंसा हो गया है। वहीं, सच बात तो यह है कि किसान आंदोलन से 10 महीने बाद भी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। सैकड़ों लोगों की नौकरी गई तो कई का तो कारोबार खत्म हो गया। रोजाना हजारों लोगों को कई किलोमीटर चल रहा अपना समय और पैसा दोनों जाया करना पड़ रहा है।

प्रदर्शनकारियों से अधिक हो गई टेंट की संख्या- वहीं, दिल्ली-हरियाणा और दिल्ली-यूपी बार्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या हजारों से सिमटकर सैकड़ों में आ गई है। टीकरी, सिंघू, शाहजहांपुर और यूपी बार्डर पर तो कभी-कभी प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या 100 से भी कम हो जाती है, जबकि टेंटों की संख्या 500 के आसपास है। कुलमिलाकर संयुक्त किसान मोर्चा भी लगता है कि उनका आंदोलन अब प्रतीकात्मक हो चुका है। कुलमिलाकर इसका कोई निष्कर्ष निकले या फिर न निकले, लेकिन सिंघु, टीकरी, शाहजहां और गाजीपुर बार्डर पर प्रतीकात्मक प्रदर्शन चलता रहे।

यूपी गेट पर भी फीका पड़ता जा रहा प्रदर्शन- उधर, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता

राकेश टिकैत की अगुवाई वाले यूपी गेट (गाजीपुर सीमा) की बात करें तो यहां पर फिलहाल बुरा हाल है। किसानों से अधिक टेंट हो गए हैं। किसान प्रदर्शनकारियों की संख्या 200 से अधिक तब होती है, जब राकेश टिकैत यहां पर आते हैं। ऐसा महीने में एकाध बार ही हो पाता है।

रास्ता रोक कर बैठे किसानों ने बढ़ाई लोगों की परेशानी- बता दें कि यूपी गेट पर भी तीनों कृषि कानूनों के विरोध में 28 नवंबर से प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यहां राष्ट्रीय राजमार्ग-नौ, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे और संपर्क मार्ग पर तंबू गाड़ कर कब्जा किया है। तंबुओं के किनारे ईंट-सीमेंट से करीब एक-डेढ़ फीट ऊंची दीवार बना दी है। पानी की टंकियां लगा दी हैं। यूपी गेट से करीब एक किलोमीटर पहले अपना खुद का चेकपोस्ट बना दिया है। इस तरह से प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से रास्ता बंद कर रखा है। कोई पैदल भी दिल्ली नहीं जा पाता है।

उधर, दिल्ली-हरियाणा के एक अन्य बार्डर यानी टीकरी बार्डर पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन सिर्फ कहने भर के लिए। टीकरी बार्डर पर आंदोलन में अब पंजाब से भी आवाजाही कम हो रही है। इसका असर भी दिखाई दे रहा है। किसान इन दिनों धान की फसलों का कार्य निपटाने में जुटे हैं। ऐसे में किसान यहां पर आने के लिए तैयार नहीं हैं। आलम यह है कि लंगर के साथ तंबू भी बहुत कम हो गए हैं।

सिंघु बार्डर पर भी रौनक गायब- सिंघु बार्डर पर फिलहाल किसान नदारद हैं। दूर तक टेंट ही टेंट नजर आते हैं, जिनमें किसान कम ही रहते हैं। यहां पर जहां कई लंगर चलते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल यहां पर किसी तंबू में अगर लंगर चल भी रहा है तो सिर्फ आसपास में ठहरे आंदोलनकारियों के लिए ही है।

तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी रखने पर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा चुका है। किसान महापंचायत से सवाल भी किया कि जब मामला विचाराधीन है तो विरोध प्रदर्शन क्यों? कानूनों पर रोक लगी हुई है और कानून लागू नहीं हैं तो फिर विरोध प्रदर्शन किसलिए? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? इसके साथ ही जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाले बंद राजमार्गों को खुलवाने के मामले में राकेश टिकैत सहित 43 आंदोलनकारी किसान संगठनों के नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 43 किसान संगठनों के नेताओं और पदाधिकारियों को पक्षकार बनाने की मांग की है, जिनमें राकेश टिकैत, दर्शन पाल, हन्नान मुल्ला, योगेंद्र यादव आदि शामिल हैं।

संपादकीय

टीकाकरण की अनकही चुनौतियां

कोविड टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए हम 12 राज्यों में 500 से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अक्तूबर के अंत तक हमारा प्रयास 20 राज्यों के 3,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ने का है, जिससे करीब 10-12 करोड़ लोगों की सेवा करने में मदद मिल सकेगी। बहरहाल, देश के टीकाकरण अभियान में लगे कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं यहां कुछ समस्याओं का जिक्र करूंगा, जो इस महत्वपूर्ण अभियान को प्रभावित करती हैं। मगर इससे पहले उन तथ्यों पर एक नजर, जिन्होंने हममें से कुछ को गुमराह किया है।

सबसे पहले तो यह धारणा पूरी तरह से गलत है कि सरकारी अधिकारियों में समर्पण और कड़ी मेहनत की कमी है। अग्रिम मोर्चे के डॉक्टरों व नर्सों से लेकर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर के अधिकारी (और मंत्री) तक, ज्यादातर लोग ऐसे काम कर रहे हैं, मानो यह जीवन-मरण का मामला हो, जो वाकई है भी। फिर, टीका को लेकर आम लोगों में उतनी झिझक भी नहीं है, जितनी अक्सर कल्पना की जाती है। एक आम परेशानी यह है कि निराधार आशंकाओं और धारणाओं के कारण लोग टीकाकरण में अरुचि दिखाते हैं। लोगों की इस उलझन को जहां संबंधित समस्याओं का हल निकालकर दूर किया जा सकता है, तो वहीं बेजा आशंकाओं से पार पाने के लिए हमें स्थानीय स्तर पर उन लोगों की मदद लेनी होगी, जिन्हें टीका लग चुका हो, और जिन पर आम लोगों का विश्वास हो। देश में टीकाकरण के लिए बुनियादी ढांचा भी पर्याप्त है। फिर चाहे वह कोल्ड चेन हो, टीके की ढुलाई हो या सुई को नष्ट करने के लिए जरूरी हब-कटर जैसे छोटे-छोटे उपकरण की उपलब्धता।

अब समस्याओं की चर्चा। पहली मुश्किल यह है कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों, दुर्गम इलाकों और बड़े शहरों की मलिन बस्तियों में टीकाकरण करने वालों की संख्या नाकाफी है। हम तकरीबन 20 फीसदी जगहों पर इस कमी का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 90 फीसदी से अधिक स्थानों पर डाटा को लेकर भी तमाम तरह की समस्याएं हैं। जैसे, धीमी इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण कंप्यूटर सिस्टम में टीकाकरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जानकारियों को दर्ज करना एक मुश्किल काम है। टीका लेने आए लोगों के दस्तावेजों की जांच करना, उनका पंजीकरण करना और फिर तमाम सूचनाओं को कंप्यूटर में लिखना, वह भी धीमी इंटरनेट के साथ, एक ऐसी प्रक्रिया हो जाती है, जिसमें टीकाकरण के बजाय आंकड़ों को जांचना व संभालना ही मूल काम बन जाता है। कई जगहों पर तो इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने के कारण टीका लेने वालों की सूचनाएं रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं और शाम में स्थानीय पीएचसी के कंप्यूटर में उनको अपलोड किया जाता है। इन आंकड़ों को दर्ज करने वाले दक्ष हाथों का भी अभाव है, इसलिए टीका लगाने वालों को ही यह काम भी करना पड़ता है, जिससे टीकाकरण करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।

दूसरी समस्या है, कंप्यूटर में दर्ज आंकड़ों में टीका लेने वाले व्यक्तियों का निवास स्थान न दर्ज होना। मान लें कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 20 गांवों व एक छोटे कस्बे की कुल 50,000 आबादी का टीकाकरण करना है, और कंप्यूटर सिस्टम उसे बताता है कि 28 हजार लोगों को टीके की पहली खुराक मिल गई है। टीके पाने वालों के नाम, उम्र, पहचान संबंधी दस्तावेज, फोन नंबर आदि सभी कंप्यूटर में दर्ज होते हैं, लेकिन जहां ये 28 हजार लोग रहते हैं, उन बस्तियों या जगहों के नाम दर्ज नहीं होते। ऐसे में, अन्य 22 हजार लोगों तक पहुंचने के लिए भला किस तरह योजना बनाई जा सकती है? यही नहीं, इन 28 हजार लोगों तक ही दूसरी खुराक के लिए हम कैसे पहुंच सकेंगे? पीएचसी कर्मी अक्सर स्थानों का पता लगाने के लिए दिन में सौ के करीब फोन करते हैं, लेकिन आमतौर पर कोई फायदा नहीं होता है। फोन नंबर गलत होते हैं, लोग ठीक-ठीक जवाब नहीं देते या फिर कनेक्शन खराब होता है। इस उदाहरण का जिक्र तो मात्र मसले को आसान शब्दों में समझाने के लिए मैंने किया है। कई मामलों में तो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास यह आंकड़ा तक नहीं होता है कि कितनी आबादी को टीका लगना है। इसीलिए उपरोक्त उदाहरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को तो यह पता ही नहीं होगा कि उसे 50 हजार लोगों का टीकाकरण करना है या इससे ज्यादा अथवा कम आबादी का, और ये लोग रहते कहां हैं।

असल में, टीकाकरण अभियान में अंतर्निहित सोच यह है कि लोग अपनी मर्जी से आएंगे और टीका लगवाएंगे। लोगों तक व्यवस्थित रूप से पहुंचने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना होगा। हालांकि, पहले के कुछ महीनों में ही यह जाहिर हो गया था कि यह एक दोषपूर्ण व्यवस्था है। लोगों तक टीके पहुंचाने के लिए व्यवस्थित, लगातार और बड़े पैमाने पर प्रयास करने होंगे। इसीलिए निवास स्थान और आबादी की सही जानकारी न होने से अराजकता पैदा हो रही है। इसकी गवाही यह आंकड़ा भी दे रहा है कि दूसरी खुराक जितने लोगों को मिल जानी चाहिए थी, उनमें करीब 25 फीसदी अब भी इससे दूर हैं। हर बीतते सप्ताह के साथ परिस्थिति-विशेष योजनाओं का निर्माण अधिक महत्वपूर्ण हो चला है। आखिरी बड़ी समस्या टीकाकरण के लिए लोगों को जुटाने के लिए स्थानीय स्तर पर टीम का न होना है। ऐसी टीमें कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकती हैं। मसलन, टीकाकरण में आने वाली बाधाओं का आकलन करना, लोगों की सुविधा के लिए काम करना, उनकी आशंकाओं को दूर करना, महामारी और टीके से जुड़ी सटीक जानकारियों का प्रचार-प्रसार करना आदि। साफ है, योजना और प्रबंधन की कमी है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक टीका पहुंचाने की योजना और प्रबंधन के अभाव के कारण हर दिन एक करोड़ खुराक लगाने और समय पर दूसरी खुराक देने का लक्ष्य मुश्किल होता जा रहा है। अंतिम 25 फीसदी आबादी का टीकाकरण तो सबसे कठिन कार्य होगा, जिनमें से अधिकांश सबसे कमजोर और वंचित तबके के लोग होंगे। हालांकि, कुछ राज्य (बहुत ही कम) व्यवस्थित ढंग से सारा काम कर रहे हैं। लेकिन यदि हम अपनी जमीनी रणनीति नहीं बदलेंगे, तो पूरे देश के टीकाकरण में हमें एक साल तक का वक्त भी लग सकता है।

प्रवीण कुमार सिंह

वजूद के संकट से जूझती कांग्रेस, नेहरू-गांधी परिवार के पास नहीं बची कोई जादुई छड़ी

> वर्ष 2000 से 2010 के बीच कांग्रेस का मत प्रतिशत 25 से 28 प्रतिशत के दायरे में झूलता रहा, जो पिछले लोकसभा चुनाव में 19.7 प्रतिशत पर आकर ठिठक गया।कुल मिलाकर कांग्रेस वजूद के संकट से जूझ रही है। जब तक अमरिंदर और पायलट जैसे जनाधार वाले नेताओं को शीर्ष पर लाकर सामूहिक नेतृत्व वाली परंपरा बहाल नहीं की जाती, तब तक कांग्रेस का भला नहीं होने वाला।नेहरू-गांधी परिवार के पास मतदाताओं को लुभाने और पार्टी का कायाकल्प करने के लिए कोई जादुई छड़ी शेष नहीं बची। जब तक अमरिंदर और पायलट जैसे जनाधार वाले नेताओं को शीर्ष पर लाकर सामूहिक नेतृत्व वाली परंपरा बहाल नहीं की जाती, तब तक कांग्रेस का भला नहीं होने वाला।

पंजाब में लगातार बदलता घटनाक्रम और राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में आकार ले रहे राजनीतिक तूफान यही संकेत करते हैं कि नेहरू-गांधी परिवार के नियंत्रण में कांग्रेस की जड़ें कमजोर होने के साथ ही उसका प्रभाव भी घट रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को फिलहाल आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी का आलाकमान इन दिनों खासा सक्रिय है। इस आलाकमान में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं। हाल में उन्होंने कांग्रेस के क्षत्रप अमरिंदर सिंह को ऐसी परिस्थितियों में अपमानित किया, जिसका पार्टी को राजनीतिक रूप से खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अमरिंदर का अपना राजनीतिक वजूद है और मतदाताओं को लुभाने के लिए वह नेहरू-गांधी परिवार के मोहताज नहीं। छत्तीसगढ़ में आलाकमान का ऐसा ही दखल राज्य में पार्टी की स्थिति को डांवाडोल कर सकता है। राजस्थान में नेहरू-गांधी परिवार सचिन पायलट की नेतृत्व क्षमता को भांपने में नाकाम रहा। वह इसे लेकर भी असहज है कि पायलट को जीतने के लिए उसके सहारे की जरूरत नहीं। यह तय है कि भविष्य में कांग्रेस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

कैप्टन अमरिंदर सिंह राजीव गांधी के सहपाठी रहे और नेहरू-गांधी परिवार से उनका वर्षों पुराना नाता है। वह नेताओं की उस पुरानी पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं, जिनके लिए आत्मसम्मान और गरिमा बहुत मायने रखती है। वह खुशामद करने वाले नेता नहीं। कांग्रेस में इंदिरा गांधी के जमाने से शुरू हुआ चापलूसी का चलन राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के समय में भी कायम है। कांग्रेस फिलहाल साढ़े-तीन लोगों की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, जिसमें सोनिया, राहुल और प्रियंका के साथ आधे हिस्सेदार राबर्ट वाड्रा भी हैं। इसमें दरबारियों का बोलबाला है। अमरिंदर जैसे कद्दावर नेता को पार्टी के प्रथम परिवार के समक्ष ही सत्ता गंवानी पड़ी।

अपने क्षत्रपों को अपमानित करने का कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। दो उदाहरण तत्काल जेहन में आते हैं। जब राजीव गांधी पार्टी महासचिव थे तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे टी अंजैया को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। फिर प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने यही सुलूक कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को हटाकर किया। अंजैया प्रकरण ने आंध्र के लोगों के आत्मगौरव पर आघात किया। इससे कांग्रेस का पराभव होता गया। परिणामस्वरूप 1982 में तेलुगु देसम पार्टी अस्तित्व में आई। तबसे राज्य में कांग्रेस अस्तित्व के संकट से जूझती आई है।

वीरेंद्र पाटिल मामले ने न केवल पार्टी की छवि पर प्रहार किया, बल्कि इससे कर्नाटक के प्रभावी लिंगायत समुदाय में भी उसका जनाधार खिसक गया। कर्नाटक में वह आज तक उस राजनीतिक झटके से उबर नहीं पाई है। हालांकि, आंध्र और तेलंगाना की तुलना में कर्नाटक में उसकी स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। पार्टी की इस दुर्गति के लिए परिवारवाद सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जो आंतरिक विमर्श से लेकर राजनीतिक संकटों का परिपक्वता से सामना करने की क्षमताएं विकसित करने की राह में अड़ंगा लगाता है।

नेहरूकालीन कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र संस्थागत रूप में विद्यमान था। कांग्रेस कार्यसमिति, संसदीय बोर्ड और संसदीय दल जैसी इकाइयों में व्यापक विचार-विमर्श की परंपरा थी। चुने हुए प्रतिनिधि ही इनका हिस्सा बनते थे। उनका मनोनयन नहीं होता था, जैसा कि बाद में पार्टी अध्यक्ष द्वारा किया जाने लगा। तब विभिन्न मुद्दों पर तीखी बहस होती थी। अधिकांश बड़े राजनीतिक फैसले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच विचार-विमर्श के बाद होते थे। फिर चाहे राज्य में मुख्यमंत्री बदलने का ही फैसला क्यों न हो। ऐसे फैसले किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नहीं होते थे। निर्णय हमेशा सामूहिक होता था। शासन के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती। पंचवर्षीय योजना, कृषि नीति या औद्योगिक नीति जैसा कोई और मसला हो, सभी पर गहन मंथन के बाद ही नीतियां बनतीं। तब ऐसा खुलापन था कि संविधान के प्रथम संशोधन संबंधी नेहरू के प्रस्ताव का 70 कांग्रेसी सांसदों ने विरोध किया और उनकी इच्छा के अनुसार ही वह संशोधन आकार ले सका। ये सब अतीत की बातें हैं।

सरकार और पार्टी पर इंदिरा गांधी की पकड़ के बाद स्थितियां बदलने लगीं। राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव वाले नेताओं को मजबूरी में ही सही सरकार का हिस्सा बनाया जाता। हालांकि, उनसे हमेशा परामर्श नहीं किया जाता। वहीं राजनीतिक रूप से रीढ़विहीन चाटुकारों को आगे बढ़ाया जाता, क्योंकि परिवार के प्रति वफादारी सबसे अधिक मायने रखती। समस्या यह भी रही कि पार्टी वोट जुटाने के लिए पूरी तरह परिवार पर निर्भर हो गई थी। यही कारण रहा कि राजनीतिक रसूख वाले कांग्रेस नेताओं ने या तो अपनी पार्टी बना ली या फिर उन दलों में शामिल हो गए जहां उन्हें बेहतर संभावनाएं दिखीं। ऐसे नेताओं की सूची बहुत लंबी है, जिन्होंने अपना राजनीतिक सफर तो कांग्रेस से शुरू किया, लेकिन बाद में अपने रास्ते अलग कर लिए। इनमें एचडी देवगौड़ा, रामकृष्ण हेगड़े, चंद्रबाबू नायडू, वीपी सिंह और ममता बनर्जी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे तमाम नाम शामिल हैं।

कांग्रेस से इन नेताओं के पलायन और चुनाव में उसके लगातार मानमर्दन में सीधा संबंध दिखता है। नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर में पार्टी लोकसभा चुनावों में 42 से 45 प्रतिशत वोटों के साथ करीब 65 प्रतिशत सीटें जीतती थी। 1957 के चुनाव में 47.8 प्रतिशत मतों के साथ उसने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया, जो रिकार्ड इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए चुनाव में 48.1 प्रतिशत मतों के साथ टूटा। ये सब इतिहास है।

वर्ष 2000 से 2010 के बीच कांग्रेस का मत प्रतिशत 25 से 28 प्रतिशत के दायरे में झूलता रहा, जो पिछले लोकसभा चुनाव में 19.7 प्रतिशत पर आकर ठिठक गया।कुल मिलाकर कांग्रेस वजूद के संकट से जूझ रही है। जब तक अमरिंदर और पायलट जैसे जनाधार वाले नेताओं को शीर्ष पर लाकर सामूहिक नेतृत्व वाली परंपरा बहाल नहीं की जाती, तब तक कांग्रेस का भला नहीं होने वाला।नेहरू-गांधी परिवार के पास मतदाताओं को लुभाने और पार्टी का कायाकल्प करने के लिए कोई जादुई छड़ी शेष नहीं बची। जब तक अमरिंदर और पायलट जैसे जनाधार वाले नेताओं को शीर्ष पर लाकर सामूहिक नेतृत्व वाली परंपरा बहाल नहीं की जाती, तब तक कांग्रेस का भला नहीं होने वाला।

हिंसा और मॉब लिंचिंग से कैसे बचेगा देश

हिंसा का जवाब सामूहिक हिंसा या मॉब लिंचिंग नहीं होती. यदि ऐसा होता तो पुलिस, क़ानून और संविधान का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता. इसीलिए 1927 में गांधी जी ने चौरीचौरा कांड के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया था. तब पुलिस की गोली से गुस्साए किसानों ने थाना फूंक दिया था. लेकिन अब फिर उत्तर प्रदेश में ऐसी सामूहिक हत्याएं (मॉब लिंचिंग) आम होती जा रही हैं. कम से कम उत्तर प्रदेश में तो यही दिख रहा है. इन सामूहिक हत्याओं पर अंकुश लगाने की बजाय सत्ता पक्ष और विपक्ष इस तरह की घटनाओं को मौन स्वीकृति देने लगा है. पिछले कुछ वर्षों से शुरू हुई ये घटनाएं अब सड़कों तक आ गई हैं. शुरू-शुरू में सेक्युलर जमात ने ऐसी घटनाओं पर हंगामा ज़रूर किया था, पर अब वो भी ऐसी घटनाओं पर आंख मूंदे हैं. शायद इसकी वजह यह है कि अब ये घटनाएं जातियों में घुस आई हैं.

कोई डेढ़ साल पहले सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ की सीमा पर यादवों और ब्राह्मणों के बीच ऐसी घटनाएं हुईं. दो सप्ताह पहले मिर्ज़ापुर में पटेलों ने एक ब्राह्मण युवक को घर से निकाला और पीट-पीट कर उसकी जान ले ली. उस ब्राह्मण युवक ने पहले एक पटेल युवक को गोली मारी थी. ताज़ा घटना लखीमपुर खीरी की है, जहां एक गाड़ी किसानों पर चढ़ गई तो किसानों ने दो गाड़ी फूंक दीं और चार लोगों को पीट-पीट कर मार दिया. इसका शिकार एक निर्दोष पत्रकार भी हो गया. निश्चय ही लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ, वह दु:खद है. हालांकि जिस तरह से किसानों के गुस्से को जायज ठहराया जा रहा है, वह कहीं न कहीं मॉब लिंचिंग को स्वीकृति है. दोनों तरफ के मृत किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए का मुआवजा देकर फिलहाल लीपा-पोती कर दी गई है. लेकिन प्रश्न यह उठता है, कि सामूहिक हिंसा पर ऐसी चुप्पी क्या संविधान परक है?

यकीनन लखीमपुर खीरी भी कुछ वैसा ही कांड है, जैसा 1927 में चौरीचौरा में हुआ था. व्यक्तिगत हिंसा के बदले में सामूहिक हिंसा. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के निर्वाचन क्षेत्र में तीन अक्टूबर को यह घटना घटी. गृह राज्यमंत्री के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का प्रोग्राम तय था. उधर तीन कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने उप मुख्यमंत्री के दौरे को रोकने का निश्चय किया. पहले तो उन्होंने उस स्थान पर धरना दिया, जहां केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था. लेकिन वे सड़क मार्ग से पहुंच गए तो किसान उनका विरोध करने उनके कार्यक्रम स्थल तक जाने की कोशिश कर रहे थे. इसी बीच एक तेज रफ़्तार गाड़ी आई और किसानों के ऊपर चढ़ गई. इसमें चार किसान मारे गए. किसानों ने ग़ुस्से में सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक कर तोड़-फोड़ शुरू की. दो गाड़ियां फूंक दी गईं और इस बदले की हिंसा में भी चार अन्य लोग मारे गए. किसानों का कहना है, कि वे लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. उन पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के समर्थकों ने गाड़ी चढ़ा दी. किसानों के अनुसार गाड़ी अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र चला रहा था. जबकि मंत्री अजय मिश्र का कहना है, कि हादसे के समय उनका बेटा न तो गाड़ी में था न वहां पर. उल्टे किसानों ने जो गाड़ियां फूंकीं उनमें उनका ड्राइवर तथा तीन और लोग मारे गए. इस घटना के बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म हो गई है और विपक्ष इस हादसे का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सक्रिय हो गया है. साथ ही पहले से ही अपनी पुलिस को लेकर कठघरे में खड़ी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और भी संकटों में घिर गई है. फ़िलहाल तो कांग्रेस, सपा और बसपा के नेताओं को नज़रबंद कर लिया गया है लेकिन उनके कार्यकर्त्ता सड़क पर उतर आए हैं. कई जगह तोड़-फोड़ और हिंसा भी हुई. अलबत्ता मृतकों के मुआवजे के बाद एक समझौता हो गया है. उत्तर प्रदेश में पांच महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं. यह चुनाव केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी बहुत अहम है. उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं. उत्तर प्रदेश की विशालता और विविधता देश की दशा और दिशा तय करती है. इसलिए न सिर्फ प्रदेश की विपक्षी पार्टियां बल्कि दूसरे प्रदेशों के राजनीतिक दल तथा कांग्रेस भी एक्टिव हो गई हैं. कांग्रेस को भी यूपी से उम्मीद है, साथ ही दूसरे प्रदेशों के विपक्षी दलों को इस बहाने तीसरे विकल्प की भी आस है. पश्चिम बंगाल से जीत कर निकलीं ममता बनर्जी और पंजाब में हाल में बनाए गए नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तथा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उत्तर प्रदेश की आंच में अपने हाथ सेकने में लगे हैं. और ये सभी नेता परोक्ष रूप से सामूहिक हिंसा को किसानों का सामूहिक गुस्सा बता रहे हैं. लेकिन सच्चाई इसके उलट भी हो सकती है.

इस सच्चाई को समझने के लिए कुछ समाज और राजनीति के दर्शन को भी समझना होगा. बीजेपी ने हिंदुत्व-हिंदुत्व कर समाज को हिंदू बनाम मुस्लिम में बांट दिया है. लेकिन वह भूल जाती है कि राजनीति कभी स्थिर नहीं होती. वह निरंतर गतिशील रहती है. बीजेपी के हिंदुत्व की काट है समाज को वर्ग के बजाय जातियों में विभाजित कर देना. आज बीजेपी के विरुद्ध सभी दल यही कर रहे हैं. किसान के बहाने उन्होंने ओबीसी समुदाय को अलग करने की ठानी है. आज किसान कौन है, सिर्फ़ ओबीसी जातियां. क्योंकि सवर्ण जातियां गांव छोड़ चुकी हैं. इसके अलावा ज़मींदारी उन्मूलन, ग्राम सुधार योजनाओं तथा मनरेगा का लाभ भी किसानों के बहाने इन्हीं ओबीसी जातियों को मिला. ये मेहनती जातियां धीरे-धीरे गांवों के सभी संसाधनों पर क़ाबिज़ हो गईं और मंडल के ज़रिए नौकरशाही में भी इनको प्रवेश मिल गया.

पुलिस अत्याचार की अति

देश के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने अफसरशाही, खासकर पुलिस ऑफिसरों की ओर से किए जा रहे अत्याचारों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश रमना ने यहां तक कह दिया कि वह राज्यों में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में ऐसी स्थायी समिति बनाने के हक में हैं, जो समय-समय पर आने वाली इन शिकायतों की जांच करे। चीफ जस्टिस रमना ने यह बात ऐसे समय कही है, जब यूपी के गोरखपुर में एक होटल पर छापे के दौरान कथित तौर पर पुलिसकर्मियों की मारपीट से हुई एक प्रॉपर्टी डीलर की मौत सुर्खियों में है। जिस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रमना ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुआई में समिति बनाने की यह बात कही, उसमें छत्तीसगढ़ के एक निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गिरफ्तारी से राहत देने की गुजारिश लेकर आए थे। इस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर राजद्रोह और अवैध वसूली समेत कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी के मुताबिक उसे पिछली सरकार से कथित तौर पर करीबी रिश्तों की सजा दी जा रही है।

इस मामले में भी पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस रमना ने पुलिस अधिकारियों में दिख रही इस प्रवृत्ति को रेखांकित किया था कि वे सत्तारूढ़ दल के नेताओं से करीबी ताल्लुकात के लिए उनके अवैध आदेशों का पालन करते हुए सारी हदें पार कर जाते हैं और फिर सत्ता बदलने पर नई सरकार का कोपभाजन बनते हैं। उन्होंने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की बात कही थी।

निश्चित रूप से यह प्रवृत्ति किसी एक मामले या एक राज्य तक सीमित नहीं है। पुलिस अधिकारियों और सत्तारूढ़ नेताओं के निजी स्वार्थों का गठबंधन ही इस पूरे खेल के पीछे है। संभवतः इस गठबंधन को तोड़ने की जरूरत महसूस करते हुए ही जस्टिस रमना ने यह बात कही कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की अगुआई में समिति बनाने का विकल्प भी उपलब्ध है। मगर देखा जाए तो यह समस्या मूलतः कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र से जुड़ी है। थोड़ी और सटीकता से कहें तो कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है और इसलिए इसे हल करने की जिम्मेदारी भी प्राथमिक तौर पर राज्य सरकारों की ही बनती है। दिक्कत यह है कि इसे हल करने की दिशा में कारगर कदम उठाना तो दूर, ऐसी कोई इच्छा भी राज्य सरकारें नहीं दिखा रहीं। जब कोई मामला मीडिया में आकर चर्चित हो जाता है तो पीड़ित पक्ष को नौकरी और नकद सहायता वगैरह देकर मामले को ठंडा कर लिया जाता है। फिर नई घटना होने तक शांति बनी रहती है। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश का समिति बनाने के विकल्प से अपनी सहमति जताना और ऐसा आदेश न देना काफी अर्थपूर्ण है। यह सभी संबंधित पक्षों के लिए गंभीर चेतावनी है। बेहतर होगा कि इस संदेश से सबक लेकर पुलिस महकमा और राज्यों का राजनीतिक नेतृत्व समय रहते अपना रवैया सुधार लें और न्यायपालिका को दखल देने की जरूरत न पड़े।

चीन के विरुद्ध बहुपक्षीय मोर्चा हो रहा तैयार, भारत-अमेरिका निभाएंगे अहम भूमिका

> मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में भारत को 'लोकतांत्रिक और भरोसेमंद साझेदार' कहा और याद दिलाया कि लोकतंत्र के साथ प्रौद्योगिकी को सुनिश्चित करना अहम आवश्यकता है। वह इशारा कर रहे हैं कि भारत और चीन में जमीन-आसमान का अंतर है और हमें चुनने के नैतिक और व्यावहारिक लाभ हैं। याद रहे कि चीन नाजी जर्मनी जैसी शक्ति नहीं है, जो दूसरे देशों पर हमला कर उन पर कब्जा कर लेगा। वह धीरे-धीरे प्रतिद्वंद्वियों पर शिकंजा कसने में जुटा है। ऐसे प्रतिद्वंद्वी से धैर्य और संयम से निपटना होगा। हम उसे उसकी ही भाषा में जवाब दें तो जरूर दबाव में ला सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपलब्धि भरी हालिया अमेरिकी यात्र ने एक सत्य को सिद्ध कर दिया है। वह यह कि चीन के विरुद्ध बहुपक्षीय मोर्चा तैयार हो रहा है और उसमें भारत एक मुख्य स्तंभ की भूमिका निभाने को तत्पर है। हालांकि, मोदी ने पूरे दौरे में सार्वजनिक तौर पर एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया, फिर भी हमारी कूटनीति निस्संदेह चीन से मुकाबले की ओर उन्मुख है। समय की भी यही मांग है। मौजूदा विश्व व्यवस्था में भारत का स्थान एक संतुलन बनाने वाली शक्ति यानी बैलेंसिंग पावर का है। हम बिना किसी संकोच के इस दायित्व के निर्वहन की पूर्ति में लगे भी हैं। वाशिंगटन में इसके स्पष्ट संकेत दिखे। वहां मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की पहली शिखर बैठक के परिणाम से साफ झलकता है कि चीन के वर्चस्व को रोकना ही विश्व के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र की व्यापक सामरिक साझेदारी का मूल सार है। वैसे तो भारत और अमेरिकी संबंधों के अनेक आयाम हैं। मसलन व्यापार, निवेश, प्रवास, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, रक्षा एवं स्वास्थ्य आदि और चीन इन सभी बिंदुओं से जुड़ा है। इस समय अमेरिका का ध्येय है चीन को विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने में विफल करना। वहीं, भारत का लक्ष्य है एशिया में चीन-केंद्रित व्यवस्था को नाकाम करना। भले ही मोदी और बाइडन ने राजनयिक औचित्य के चलते चीन का खुलकर जिक्र न किया हो, फिर भी उनके साझा संयुक्त बयान में हिंद-प्रशांत का उल्लेख पांच बार हुआ है। इसका सीधा तात्पर्य चीन को चुनौती देना है।

अफगानिस्तान को लेकर बाइडन का रवैया भले निराशाजनक रहा हो और उससे भारत की भूराजनीतिक स्थिति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को ठेस पहुंची हो, परंतु इससे यह अनुमान लगाना गलत है कि अमेरिका हिंद-प्रशांत में भी मित्र राष्ट्रों का परित्याग कर भाग निकलेगा। उधर चीन इसी प्रचार में लगा है कि ताइवान हो या एशिया में अन्य अमेरिकी साझेदार, सबको अफगानिस्तान से सबक लेना चाहिए कि अमेरिका गैर-भरोसेमंद है और उसके सहारे की आस में चीन का विरोध करना मूर्खता है। बाइडन की नीतियों से इतना स्पष्ट है कि चाहे दुनिया भर से अमेरिका पीछे लौट जाए, परंतु हिं-प्रशांत को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ऐसा करना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अमेरिका ने हाल में ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के साथ आकस नाम से नया सैन्य गठबंधन बनाया है। इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में 21वीं सदी के खतरों यानी चीनी विस्तारवाद का प्रतिरोध करने की क्षमताएं बढ़ने की बात कही जा रही हैं। हालांकि, हिंद-प्रशांत में ब्रिटेन की सीमित ताकत और इसमें एशियाई देशों की अनुपस्थिति से आकस का चीन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर बाइडन ने भारत के साथ हिंद-प्रशांत और अफ्रीका में त्रिकोणीय विकास सहयोग पर जोर दिया है।

इससे दोनों पक्ष मिलकर चुनिंदा विकासशील देशों मे कृषि, क्षेत्रीय संपर्क, स्वास्थ्य, आपदा तैयारी, ऊर्जा और पोषण जैसे क्षेत्रों मे परियोजनाएं चलाएंगे। भारत और अमेरिका सहमत हैं कि इससे हिंद-प्रशांत में चीनी आक्रामकता के बरक्स 'क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनों' का बचाव किया जा सकता है। बाइडन चीन के खिलाफ दूरगामी रणनीति और सामरिक धैर्य वाला दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। वैसे भी केवल सैन्य आक्रामकता से चीन के कद पर प्रहार नहीं किया जा सकता।

चीनी विस्तारवाद के कुछ मुख्य बिंदु हैं उसकी भीमकाय इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, आर्थिक विकास के नाम पर कर्ज का जाल और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कमजोर देशों पर नियंत्रण। उसकी इन बलाओं से मुक्ति दिलाने में भारत और अमेरिका सहित जापान और आस्ट्रेलिया जैसे क्वाड के सभी सदस्य देश चाहते हैं कि एक वैकल्पिक ढांचा बने, जो बहुआयामी और दीर्घकालिक हो। क्वाड की पहली औपचारिक बैठक में इसके स्पष्ट संकेत मिले। क्वाड बैठक का एक विशेष परिणाम था प्रौद्योगिकी में साझा पहल, जो 'सार्वभौमिक मानवाधिकारों और मूल्यों' का संरक्षण करेगी। इस अवसर पर चारों साथियों ने '5जी विविधीकरण' का प्रण लिया और 'भरोसेमंद विक्रेताओं' को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई।

दरअसल, हुआवे और जेडटीई जैसी चीनी दिग्गज कंपनियों ने कई विकासशील देशों में 5जी का ढांचा तैयार कर इस दिशा में बढ़त बनाई है। इसी आड़ में चीन इन देशों के दूरसंचार जैसे संवेदनशील क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। इसीलिए क्वाड सदस्यों ने सेमीकंडक्टर उत्पादन में विविधतापूर्ण एवं सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने का फैसला किया, ताकि चीनी दबदबे को घटाया जा सके। साथ ही ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे लोकतांत्रिक आपूर्तिकारों की क्षमताएं बढ़ें। भारत भी सेमीकंडक्टर उत्पादन में उतरने की तैयारी कर रहा है। इसी लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में मोदी ने अमेरिकी चिप महारथी क्वालकाम के मुखिया से मुलाकात की। चीन के विरुद्ध नए शीतयुद्ध में भारत को लोकतांत्रिक पश्चिमी देशों से अधिक विदेशी निवेश मिले तो इससे हमारा आर्थिक विकास भी होगा और वैश्विक शक्ति संतुलन भी सधेगा। जब से ट्रंप प्रशासन ने चीन को निशाना बनाते हुए आर्थिक जंग शुरू की तबसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने 'चीन प्लस वन' रणनीति बनाई है। इससे वे अकेले चीन मे निवेश करने के बजाय अन्य देशों मे भी निवेश कर भूराजनीतिक जोखिमों को घटा रही हैं। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में भारत को 'लोकतांत्रिक और भरोसेमंद साझेदार' कहा और याद दिलाया कि लोकतंत्र के साथ प्रौद्योगिकी को सुनिश्चित करना अहम आवश्यकता है। वह इशारा कर रहे हैं कि भारत और चीन में जमीन-आसमान का अंतर है और हमें चुनने के नैतिक और व्यावहारिक लाभ हैं। याद रहे कि चीन नाजी जर्मनी जैसी शक्ति नहीं है, जो दूसरे देशों पर हमला कर उन पर कब्जा कर लेगा। वह धीरे-धीरे प्रतिद्वंद्वियों पर शिकंजा कसने में जुटा है। ऐसे प्रतिद्वंद्वी से धैर्य और संयम से निपटना होगा। हम उसे उसकी ही भाषा में जवाब दें तो जरूर दबाव में ला सकते हैं। ऐसे में सवाल यह नहीं होना चाहिए कि क्वाड एक सैन्य गठबंधन क्यों नहीं बन पाया, बल्कि यह होना चाहिए कि चीन को मात कैसे दी जाए? भारत सही सवाल और सही जवाब के पथ पर है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह, टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

पुष्कर में दुर्गा पूजा महोत्सव से पहले एक कलाकार देवी दुर्गा की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा का बड़ा आरोप- मुझे गैर कानूनी रूप से रखा है कैद, 53 घंटे बाद भी नहीं बता पाई पुलिस

लखनऊ । लखीमपुर कांड के बाद से पीड़ित परिवारों से मिलने की जिद पर अड़ी कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने अपनी हिरासत को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बयान जारी कर आरोप लगाया है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से बलपूवर्क हिरासत में लिया गया। बिना किसी कानूनी आधार के उनके सांविधानिक अधिकारों का हनन करते हुए उन्हें सीतापुर पीएसी गेस्ट हाउस में कैद रखा गया है। वहीं, सीतापुर जिला प्रशासन ने सुबह आठ बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है।

प्रियंका वाड्रा सोमवार सुबह साढे चार बजे से सीतापुर पुलिस की हिरासत में हैं। बुधवार सुबह उ?हें हिरासत में लगभग 53 घंटे से ज?यादा हो गए हैं। गेट के बाहर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। रात में पीएससी गेटस हाउस के बाहर 15 मिनट के लिए लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से वहां हलचल बढ़ गई। कार्यकर्ताओं को कुछ अप्रिय घटना का संदेह लगा था, लेकिन फिर स्थिति सामा?य हो गई। प्रियंका वाड्रा अभी भी लखीमपुर जाने के लिए अड़ी हुई हैं।

रविवार रात को ही लखनऊ आकर लखीमपुर के लिए रवाना हुईं कांग्रेस महासचिव को पुलिस-प्रशासन ने सीतापुर में हिरासत में ले लिया था। वह ऐलान कर चुकी हैं कि लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के परिवारों से मिले बिना वापस नहीं जाएंगी। मंगलवार दोपहर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी किया और फिर देर शाम प्रियंका ने अपना लिखित वक्तव्य जारी किया, जिसमें विस्तार से घटनाक्रम बताया है।

प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि चार अक्टूबर यानी सोमवार सुबह लगभग 4.30 बजे सीतापुर के सीओ पीयूष कुमार सिंह के मौखिक कथन पर उन्हें धारा 151 के तहत हिरासत में लिया गया। उस वक्त वह लखीमपुर जिले की सीमा से बीस किलोमीटर दूर थीं। सीतापुर में धारा 144 लागू नहीं हुई थी। वैसे भी वह दो कार्यकर्ता, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और निजी सचिव संदीप सिंह के साथ गाड़ी से जा रही थीं। चार लोगों के अलावा सुरक्षा दस्ता तक साथ नहीं था। तब भी हिरासत में लेकर दो महिला और दो पुरुष कांस्टेबल सीतापुर पीएसी परिसर ले आए।

कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी ने स्पष्ट कहा है कि पीएसी परिसर लाए जाने के बाद से अब तक पुलिस, प्रशासन या सरकार ने यह नहीं बताया कि उन्हें किन कारणों से और किन धाराओं में हिरासत में लिया गया है। हिरासत से संबंधित कोई नोटिस, आदेश या एफआइआर नहीं दिखाई गई। कांग्रेस नेता के मुताबिक, उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर एक कागज देखा है, जिसमें प्रशासन ने 11 लोगों को नामजद किया है, जिनमें से आठ लोग तो उनकी हिरासत के वक्त वहां मौजूद ही नहीं थे। प्रशासन ने उन दो लोगों को भी नामजद कर दिया, जो लखनऊ से सिर्फ कपड़े देने आए थे। प्रियंका ने कहा है कि उन्हें किसी मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी के सामने पेश नहीं किया गया। उनके वकील गेट पर खड़े हैं, लेकिन कानूनी सलाह लेने के लिए वकीलों से मिलने के अधिकार से वंचित रखा गया।

संक्षिप्त खबर

लखीमपुर खीरी हिंसा पर सियासी घमासान, राहुल के लखनऊ आने से पहले यूपी सरकार की दो टूक- माहौल बिगाड़ने नहीं देंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तो दंगल से पहले ही हिंसा हो गई, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच घटना के बाद से ही कुश्ती जारी है। यूपी के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले ही हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद विपक्षी दलों में पहले पीड़ित और घटनास्थल तक पहुंचने की होड़-दौड़ रविवार से ही शुरू हो गई और आज बुधवार को भी जारी है। पहले दिन रात में ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा दिल्ली से लखनऊ पहुंचकर लखीमपुर के लिए रवाना हो गईं, लेकिन सीतापुर में रोक कर हिरासत में ले ली गईं। लखीमपुर खीरी जाने के ऐलान के बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट से लौटा दिया गया। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव लखनऊ में सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरे, जो हिरासत में लेकर बाद में छोड़ दिए गए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी सीतापुर में हिरासत में ले लिए गए। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी लखीमपुर जाने की कोशिश में हैं। हालांकि सरकार ने उनकी तरफ से लखीमपुर खीरी जाने को लेकर मांगी गई अनुमति को खारिज कर दिया है। लखनऊ में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई है।

असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देगी योगी सरकार, दुर्घटना में मौत व स्थायी दिव्यांगता पर मिलेगी दो लाख रुपये बीमा राशि

लखनऊ । राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये तक का बीमा कवर मुहैया कराने का फैसला किया है। पंजीकृत मजदूरों व उनके परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्णय किया है। यह सुविधा उप्र असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक पंजीकृत हो चुके कामगारों और केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को मिलेगी। श्रम विभाग के प्रस्ताव पर फैसले की जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ ड्क्षसह ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी दुर्घटना में मृत्यु या शत-प्रतिशत दिव्यांगता पर दो लाख रुपये तक की बीमा राशि देने का प्राविधान है। वहीं 50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर एक लाख रुपये और 25 से 50 फीसद तक दिव्यांगता पर 50 हजार रुपये बीमा राशि दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर शुरू की गई मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों को साल में पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की निश्शुल्क सुविधा मिलेगी। उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड इस योजना का क्रियान्वयन स्टेट एजेंसी कंप्रीहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के माध्यम से कराएगा। इसके लिए बोर्ड और साचीज के बीच अनुबंध होगा। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की अनुमानित संख्या 4.5 करोड़ है। उप्र असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक 79,215 श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 24 लाख से ज्यादा श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं।

मांझी ने लालू यादव पर किया हमला- बोले-उपचुनाव से पहले मुझसे डर गए आरजेडी सुप्रीमो

पटना। बिहार की दो सीटों कुशेश्वरस्थान और तारापुर पर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सहमति के बाद पार्टी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर कांग्रेस को झटका दे दिया। राजद के इस स्टैंड को कांग्रेस ने गलत करार दिया और दोनों सीटों से अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। महागठबंधन की इस रस्साकशी के बीच हिन्दुस्तानी आवाम पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव पर सियासी हमला किया है। मांझी ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा है कि, लालू प्रसाद का ये डर अच्छा है। बिहार की दो विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सियासी बयानबाजी का दौर भी तेजी से शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में हिन्दुस्तानी आवामी मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर बड़ा हमला किया है। मांझी ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा है कि, जब लालू यादव सीएम थे, उस दौरान मैंने दशरथ मांझी जी को सम्मान देने के लिए कई बार कहा, लेकिन उनका जवाब ही अलग था। मांझी ने आगे लिखा है कि, लालू यादव का ये डर अच्छा है।

मंगलवार को आरजेडी के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को दिल्ली से लालू यादव ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया था। इस दौरान लालू यादव ने उपचुनाव को लेकर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि, जब मैं बिहार का सीएम था तो उस वक्त समाज में सबसे पिछड़ी कहे जानी वाली मुसहर जाति के लिए बहुत सारे काम किए थे। उपचुनाव को लेकर जातीय समीकर बताते हुए राजद सुप्रीमो ने कहा था कि, कुशेश्वरस्थान विधानसभा में यादव, अन्य जाति के साथ-साथ मुसहर जाति की भी अच्छी आबादी है। पार्टी ने गणेश भारती को इस वजह से टिकट दिया गया है, ताकि, इस इलाके के पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बिहार सीएम नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद, भाजपा पर लगाए आरोप

पटना । जन अधिकार पार्टी (जाप) सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें भाजपा और अस्पताल माफिया के दबाव में गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस में जाप के विलय को लेकर उन्होंने कहा कि राजद से कांग्रेस अलग होती है तो वे कांग्रेस को हर सहयोग करने को तैयार हैं। करीब पांच महीने जेल में रहने के बाद मंगलवार को पटना पहुंचे और प्रेस से बात कर रहे थे। जाप प्रमुख ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जेल में रहने के दौरान मेरे स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा गया। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाए कि एक विपक्षी पार्टी ईडी-सीबीआइ के डर से भाजपा से नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार से सवाल करती है। इसी वजह से ईडी-सीबीआइ इनकी संपत्ति जब्त नहीं करती। उन्होंने कहा, कांग्रेस अगर राजद से अलग होती है तो

यूपी के एक करोड़ स्टूडेंट्स को टैबलेट व स्मार्टफोन देगी यूपी सरकार, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

लखनऊ । युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित व स्वावलंबी बनाने के लिए योगी सरकार उन्हें मुफ्त में स्मार्ट फोन और टैबलेट देकर सशक्त व समर्थ बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरण योजना को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि युवाओं के डिजिटल सशक्तीकरण के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है। सरकार से यह सौगात पाने वाले युवाओं की संख्या 60 लाख से एक करोड़ तक हो सकती है। इस पर 3000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि टैबलेट व स्मार्टफोन स्नातक, परास्नातक, बीटेक, डिप्लोमा, पैरामेडिकल व नर्सिंग और कौशल विकास से जुड़े लाभार्थी युवा छात्रों को बांटे जाएंगे। इससे न केवल वे अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे, बल्कि उसके बाद विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी तथा स्वावलंबन की योजनाओं में भी इसका सदुपयोग कर नौकरी व रोजगार पा सकेंगे। कोरोना काल में आनलाइन शिक्षा, ट्यूटोरियल व कोचिंग अपरिहार्य हो गए हैं।

इस योजना का लाभ कौशल विकास विभाग के सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत व चिन्हित एजेंसियों के जरिये प्लंबर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक आदि सेवाएं देने वाले कुशल कारीगरों को भी दिया जाएगा। योजना के तहत प्रस्तावित लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय-समय पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से शामिल किया जा सकेगा। किस लाभार्थी वर्ग को टैबलेट देना है और किसे स्मार्टफोन, इसका निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे।टैबलेट व स्मार्ट फोन के वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण तथा चरणबद्ध क्रय के सम्बन्ध में भी निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा। भविष्य में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए योजना में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। छात्रों को टैबलेट व स्मार्टफोन के वितरण के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। चिन्हित शिक्षण संस्थानों की ओर से छात्रों की सूची समिति को उपलब्ध कराई जाएगी। टैबलेट व स्मार्टफोन जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदे जाएंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए औद्योगिक विकास विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की कोशिश है कि टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरण के लिए नवंबर के पहले हफ्ते तक छात्रों की सूची तैयार कर ली जाए।

गौरतलब है कि योगी सरकार ने युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन देकर उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट में 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में सत्ता में आने पर कॉलेज में दाखिला लेने वाले सभी युवाओं को मुफ्त लैपटाप देने का ऐलान किया था।

कानपुर के सर्किट हाउस में लगेगी अटल की प्रतिमा = लोक भवन के बाद अब भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक और प्रतिमा लगाई जाएगी। यह प्रतिमा कानपुर नगर के सर्किट हाउस में लगाए जाने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रतिमा की स्थापना के लिए कुल लागत 37.35 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत प्रतिमा की स्थापना, प्लेटफार्म का निर्माण कार्य, स्टील की रेलिंग व अन्य कार्य सम्मिलित होंगे। प्रतिमा की आपूर्ति व स्थापना से जुड़े कार्यों के लिए प्रस्तावित 22.05 लाख रुपये में कुछ अन्य कार्यों को सम्मिलित करते हुए कुल 37.35 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा लगाई गई थी, जिसका अनावरण 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।

चित्रकूट पर्यटन व धार्मिक स्थल क्षेत्र को फ्री जोन घोषित = प्रदेश सरकार ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र चित्रकूट में उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश की सीमाओं की बंदिशें खत्म करते हुए पर्यटन व धार्मिक स्थल क्षेत्र को फ्री जोन घोषित कर दिया है। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को दोनों प्रदेशों के बीच हुए करार के तहत वाहनों को एक दूसरे के यहां आने-जाने के लिए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित कुछ क्षेत्रों को वाहनों को कर से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामघाट को केंद्र मानते हुए दस किलोमीटर की परिधि में यह छूट होगी। इससे श्रद्धालु बगैर अतिरिक्त कर चुकाए बेरोकटोक आ-जा सकेंगे।

वाराणसी के दो मार्ग होंगे चौड़े, जाम से मिलेगी राहत = वाराणसी के लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने व देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की राह आसान करने के लिए कैबिनेट ने दो प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्यों को मंजूरी दे दी है। इन निर्माण कार्य से शहर वासियों को रोजाना के जाम से बड़ी राहत मिल सकेगी।कैबिनेट ने वाराणसी में मोहनसराय दीनदयाल उपाध्याय नगर चकिया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-120) के चैनेज 0.000 से 10.200 के मध्य सर्विस लेन के साथ छह-लेन तथा चैनेज 10.200 से 11.180 के मध्य चार-लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (लंबाई 11.180 किलोमीटर) के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 412.53 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह मार्ग बीएचयू, डीएलडब्ल्यू, वाराणसी कैंट रेलवे व बस स्टेशन, सारनाथ, चंदौली, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। वाराणसी में वीआइपी मूवमेंट, देश-विदेश से पर्यटकों व श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार रहता है। इस मार्ग पर यातायात घनत्व अत्यधिक होने के कारण अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा वाराणसी-भदोही-गोपीगंज मार्ग के चैनेज 4.310 से 12.910 तक चार-लेन चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (लंबाई 8.600 किलोमीटर) कार्य के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 269.10 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वाराणसी-भदोही-गोपीगंज मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-87) के चैनेज 0.00 से 4.310 तक का भाग सघन शहरी क्षेत्र है। मार्ग का चैनेज 4.310 मोहनसराय दीनदयाल उपाध्याय नगर चकिया मार्ग से चांदपुर चौराहा (कलेक्ट्री फार्म) पर स्थित है। मार्ग के चैनेज 4.310 से 12.910 तक का भाग चांदपुर चौराहा (कलेक्ट्री फार्म) से वाराणसी रिंग रोड फेज-दो को जोड़ता है। मार्ग का यह भाग रिंग रोड व विश्वविख्यात कालीन निर्माण केंद्र भदोही से वाराणसी शहर का प्रवेश मार्ग है।

गांठ तो हो गई पर चलता रहेगा राजद और कांग्रेस का गठबंधन, भाजपा-जदयू के तानों पर नहीं देंगे ध्यान

पटना। बिहार में विपक्षी दलों के सबसे बड़े गठबंधन में गांठ भले पड़ गई है, लेकिन बंधन अभी टूटा नहीं है। विधानसभा की दो सीटों तारापुर और कुशेश्वरस्थान के लिए होने वाले उपचुनाव में राजद और कांग्रेस ने भले ही एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन दोनों ही दल अभी गठबंधन टूटने की बात नहीं कह रहे हैं। राजद के नेताओं ने औकात और हैसियत तक बात पहुंचाई, भाजपा और जदयू के नेता तंज कसते रहें, लेकिन कांग्रेस अभी अपने सहयोगी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। इसका पता इस बात से चलता है कि पप्पू यादव की शर्त पर कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चर्चाएं हैं कि कांग्रेस ने पप्पू यादव को तारापुर सीट से चुनाव लड़ने का आफर दिया था। इसके बाद पप्पू ने कहा कि वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं बशर्ते पार्टी राजद से अपना नाता तोड़ ले।

पप्पू यादव की शर्त पर राजी होने की बजाय कांग्रेस ने तारापुर सीट से दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। इससे लगता है कि कांग्रेस ने भले ही अपनी नाक बचाने के लिए विधानसभा की दोनों सीटों पर राजद के खिलाफ अपना उम्मीदवार दे दिया, लेकिन दोनों दलों का साथ अभी बना रहेगा। तेजस्वी यादव ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। दोनों सीटों पर राजद-कांग्रेस के आमने-सामने होने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि यह तो उप चुनाव है। चर्चाएं हैं कि दोनों दलों के रिश्तों में यह गांठ कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री की वजह से हुई है।

इधर, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि बिहार में होने वाले किसी भी चुनाव से पहले कांग्रेस के कुछ नेता राजद को आंख दिखाने की नौटंकी करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में अपने कहे को पूरा करने की रत्ती भर भी हिम्मत नहीं है। इस तरह के बयानों से इनके नेता कार्यकर्ताओं के सामने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी है कि अगर वह राजद से नहीं डरते हैं तो महागठबंधन से अलग हटने का ऐलान करें। राजीव रंजन ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस का पूरा अस्तित्व राजद पर टिका हुआ है। इनके पास न तो जनाधार बचा है और नहीं जनाधार वाले नेता, दूसरी तरफ राजद जब चाहे इनकी पार्टी के इतने टुकड़े कर दे कि कोई पंजे का झंडा उठाने वाला भी नहीं बचेगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि राजद का इतिहास और चरित्र गठबंधन के साथियों को धोखा देना रहा है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो भाजपा के सहयोग से बने, जिसके बदले में लालू ने भाजपा को धोखा दिया। झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी झामुमो को धोखा दिया। वीआइपी प्रमुख मुकेश साहनी की पार्टी को धोखा दिया और अब कांग्रेस को औकात पर ला कर खड़ा कर दिया है।

आखिरकार चारों किसानों का हो गया अंतिम संस्कार, तड़के हुआ चौथे का पोस्टमार्टम

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा के दौरान मृत चार किसानों में तीन का मंगलवार को अंतिम संस्कार दिया गया लेकिन बहराइच का मोहरनिया निवासी परिवार दोबारा पोस्टमार्टम पर अड़ा गया। मोहरनिया के मृत किसान गुरुविंदर सिंह के परिवारजन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत करार देते हुए मृतक को गोली मारने की बात कही। देर शाम राकेश टिकैत मृत किसान गुरुविंदर सिंह के घर पहुंचे। स्वजन मृतक का दोबारा दिल्ली में पोस्टमार्टम कराने की जिद कर रहे थे। आखिरकार तड़के चार बजे दोबारा पोस्टमार्टम के बाद मोहर्नियां में मृत किसान का अंतिम संस्कार करा दिया गया।

मृतक किसान गुरुविंदर के दोबारा पोस्टमार्टम की मांग पर लखनऊ से चार सदस्यीय चिकित्सकों की टीम हेलीकाप्टर से बहराइच पहुंची, लेकिन किसान नेता व परिवारजन शव दिल्ली ले जाने की मांग कर रहे हैं। परिवार ने कहा कि गोली मारी गई। गुरुविंदर के पिता सुखविंदर सिंह का आरोप था कि बेटे की हत्या गोली मार कर की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। गोरखपुर के एडीजी जोन अखिल कुमार ने परिवारजन से बात कर दोबारा चिकित्सकों की टीम से पोस्टमार्टम कराने का भरोसा दिया, लेकिन मौके पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत व परिवारजन शव को एयर लिफ्ट कराकर दिल्ली में दोबारा पोस्टमार्टम की बात पर अड़े रहे। टिकैत ने कहा कि संयुक्त मोर्चा एवं पीड़ित परिवार की मांग के अनुरूप फैसला होना चाहिए। आखिरकार अधिकारी देर रात मृतक के परिवारजन को समझाने में सफल रहे। परिवारजन की मांग के मद?देनजर बुधवार को भोर में जिला मुख्यालय पर चिकित्सकों के विशेष दल ने पोस्टमाटम किया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच शव को मोहर्निया गांव ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। लखीमपुर खीरी में चौखड़ा निवासी लवप्रीत और धौरहरा नक्षत्र सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस एवं प्रशासन के उच्चाधिकारियों व किसान नेताओं की उपस्थिति में दाह संस्कार हुआ। पहले परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत होने का आरोप लगाकर दाह संस्कार करने से मना कर दिया था। इसके बाद किसान वहां पर जमा होने लगे थे। किसान नेता राकेश टिकैत भी चौखड़ा फार्म पहुंच गए थे। काफी देर तक जिद्दोजहद चलने के बाद स्वजन व किसान लवप्रीत के शव को लेकर मझगईं आ गए और वहां पर मार्ग जाम कर दिया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और विश्वास दिलाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। बाद में परिवारजन व किसान नेता दाह संस्कार करने पर राजी हो गए। जबकि नानपारा कोतवाली के बंजारन टाड़ा निवासी दलजीत सिंह का मंगलवार को शव आने के बाद प्रशासन के समझाने पर अंतिम संस्कार देर शाम हो गया। टिकैत पहुंचे मृतक पत्रकार रमन कश्यप के घर = मंगलवार को राकेश टिकैत निघासन में मृतक पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे और मृतक के परिवार से मिलकर ढांढ़स बंधाते हुए कहा कि हमारी संवेदना आपके साथ है।

यूपी पुलिस ने दुर्गा पूजा व दशहरा को लेकर जारी की गाइडलाइन, पीएसी व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल रहेगा मुस्तैद

लखनऊ । लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी शांति-व्यवस्था की चुनौती बढ़ती जा रही है। लखनऊ और सीतापुर में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच पुलिस प्रशासन की निगाहें अब कई अन्य संवेदनशील जिलों पर टिकी हैं। खुफिया तंत्र को सक्रिय किए जाने के साथ ही कई जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने के दिश-निर्देश दिए गए हैं। खासकर सात अक्टूबर से शुरू हो रही नवरात्रि और 15 अक्टूबर को दशहरा की शांति-व्यवस्था किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगी। यही वजह है कि इस बाद दुर्गापूजा, रामनवमी व दशहरा की सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर कड़े बंदोबस्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान 183 कंपनी पीएसी व पांच कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती होगी। इसे लेकर डीजीपी मुख्यालय स्तर से कई कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा, राम नवमी व दशहरा की सरक्षा-व्यवस्था को लेकर कडे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। कहीं भी अफवाह फैलाने अथवा गड़बड़ी करने वालों से पुलिस पूरी सख्ती से निपटेगी। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस और पीएसी मुस्तैद की जाएगी। इस दौरान पांच कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी अलग-अलग स्थानों पर तैनात रहेगा। इंटरनेट मीडिया की निगरानी के कड़े निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर में कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की हत्या के बाद पुलिस की कार्यशैली कठघरे में थी। मनीष हत्याकांड में पुलिस कार्रवाई के कदम बढ़ाए जाने के दावे कर स्थिति को कुछ हद तक संभाल सकी थी। अब लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा ने पुलिस की मुश्किलें अचानक काफी बढ़ा दी हैं। ऐसे में शरारती तत्वों व इंटरनेट मीडिया के जरिए भ्रामक सूचनाओं का प्रसार करने वालों पर भी कड़ी निगाह रखनी होगी। सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर व्यापक रणनीति बनाई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती हापुड़, कानपुर कमिश्नरेट, लखनऊ कमिश्नरेट, गोरखपर व मऊ में तैनात रहेंगी।

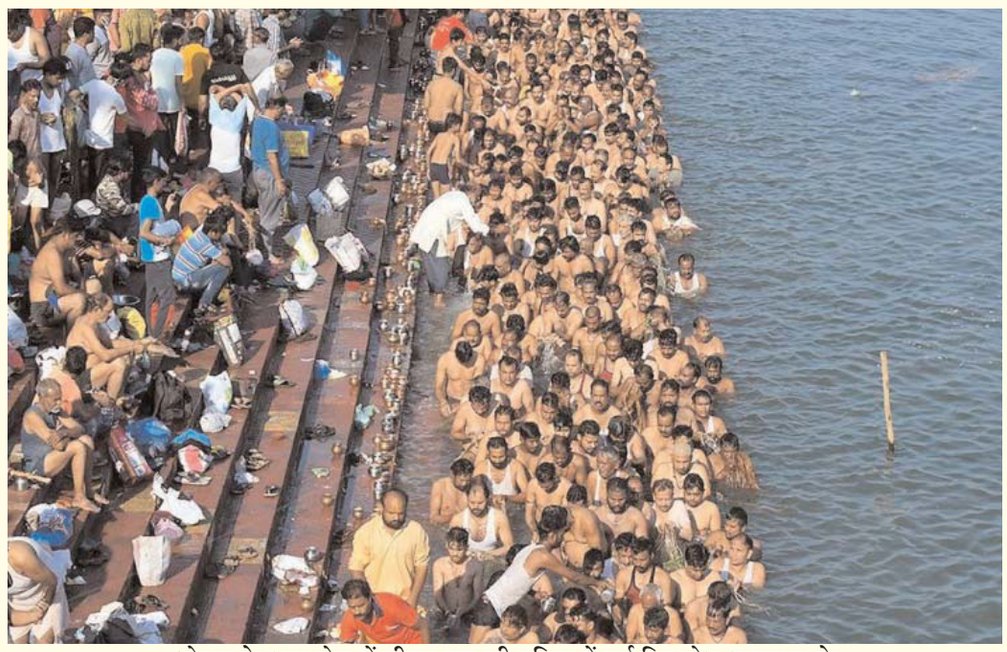

भोपाल के अपर लेक में शीतल दास की बगिया में सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त तर्पण करते हुए।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को हरदा में स्वामित्व योजना कार्यक्रम में ग्रामीणों को अधिकार अभिलेख वितरित किए। हरदा में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम पटेल और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। वहीं मध्यप्रदेश से संबंधित केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में शामिल हुए।

शिवराज जी ने गरीब कल्याण योजना के माध्यम से शुरू की थी जनसेवा

भोपाल (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे संतोष है कि मध्यप्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना कागज आसानी से मिल रहा है। नागरिकों को आबादी की भूमि पर मालिकाना हक देकर उन्हें सशक्त और आत्म-निर्भर बनाया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि मध्यप्रदेश में जल्द ही सभी गांवों में अधिकार अभिलेख मिल जाएंगे।

हरदा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी

पीएम मोदी बुधवार स्वामित्व योजना में मध्यप्रदेश के 19 जिलों के तीन हजार गांव के एक लाख 71 हजार ग्रामीणों को वर्चुअली अधिकार अभिलेखों का वितरण कर संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। हरदा जिला मुख्यालय पर आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों सहित प्रदेश के मंत्री भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अधिकार अभिलेखों का वितरण कर हरदा, डिंडौरी और सीहोर जिले के अधिकार अभिलेख प्राप्त हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने सबसे पहले गरीब कल्याण योजना के माध्यम से जनसेवा की नई शुरुआत की थी। शिवराज जी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में टेक्नालॉजी के उपयोग के साथ कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को हरदा जिले के पवन कुमार, डिंडौरी जिले के प्रेमसिंह और सीहोर जिले की विनीता बाई से संवाद किया।

मोदी के पीएम और सीएम के रूप में 20 वर्ष पूर्ण

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज के दिन ही नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में 20 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किए जा रहे हैं।

380 आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने हरदा जिले में सौर ऊर्जा से रौशन हुए 380 आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने हरदा प्रशासन के इस नवाचार की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हरदा जिले की विकास गाथा पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री और किसानों ने मुख्यमंत्री को कृषि यंत्र हल भेंट किया। कार्यक्रम में हरदा जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, कृषि मंत्री कमल पटेल, वन मंत्री डॉ. विजय शाह, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सांसद दुर्गादास उइके सहित विधायक मौजूद थे।

स्वामित्व योजना से लोग लखपति बन जाएंगे : पटेल

कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि ग्रामीण सम्पति धारकों की जिस संपत्ति का मूल्य अभी सरकारी अभिलेख में शून्य था, वह लाखों में हो जाएगा और छोटी से छोटी संपत्ति के धारक ग्रामीण स्वामित्व योजना के माध्यम से लोग लखपति बन जाएंगे।

बैंक से ऋण लेना आसान होगा : गोविंद सिंह

प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत आबादी सर्वे से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के अधिकार अभिलेख उपलब्ध हो जाएंगे। स्वामित्व प्रमाण-पत्र मिलने से इस संपत्ति पर बैंक से ऋण लेना आसान होगा तथा संपत्तियों के पारिवारिक विभाजन व सम्पति हस्तांतरण की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी।

स्वामित्व योजना के लाभ

- स्वामित्व योजना के तहत अधिकार पत्र मिलने से बैंक लोन मिल सकता है।
- जमीन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र होने कानूनी रूप से हितग्राही मालिक होगा।
- संबधित जमीन पर अपने हिसाब मकान बनाने की अनुमति मिलेगी।
- ग्रामीणों इलाकों में प्राईवेट और सरकारी जमीन की जानकारी सुलभ मिलेगी।
- जमीन-संपत्ति के लिए होने वाले विवाद समाप्त होंगे।
- जमीन और भवन के बंटवारे और नामांतरण आसानी होंगे ।
- सरकारी भवन का निर्माण सही योजना से होगा।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल ने किया मां नर्मदा स्तुति के लोकगीतों का शुभारंभ

भोपाल । राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने बुधवार को नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर मां नर्मदा मंदिर में पूजा अर्चना की और आरती के बाद लोक संस्कृति पर आधारित मां नर्मदा की स्तुति का शुभारंभ किया। स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा मां नर्मदा की लोक संस्कृति पर आधारित यह स्तुति प्रातः एवं संध्या काल में मां नर्मदा की आरती के पश्चात लोक कलाकारों द्वारा की जाएगी। लोक संस्कृति पर आधारित मां नर्मदा स्तुति का प्रशिक्षण नर्मदा मां सेवा समिति के धनराज सिंह द्वारा दिया गया। लोक कलाकारों ने नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मां नर्मदा की पूजा अर्चना के बाद लोक संस्कृति पर आधारित मां नर्मदा की स्तुति की प्रस्तुति दी। राज्यपाल ने अमरकंटक में पवित्र नर्मदा मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश के नागरिकों की सुख समृद्धि की कामना की।

सीएम ने खंडेलवाल की पुण्यतिथि पर किया नमन

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्व. प्यारेलाल खंडेलवाल की पुण्य-तिथि पर उन्हें नमन किया। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री निवास स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य रहे, वरिष्ठ नेता स्व. प्यारेलाल खंडेलवाल की पुण्य-तिथि पर उन्हें स्मरण करते हुए ट्वीट किया है कि 'राष्ट्र एवं जनसेवा के अपने कार्यों के माध्यम से आप सदैव जन-जन के हृदय में रहेंगे। श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल का जन्म 6 अप्रैल, 1929 को ग्राम चारमंडली जिला सीहोर में हुआ था। उन्होंने इंदौर में क्रांतिकारियों और देशभक्तों के समूह, प्रजामंडल द्वारा प्रकाशित गुप्त पर्चों का वितरण एवं माहेश्वरी विद्यालय में विद्यार्थी आन्दोलन को अपना प्रखर नेतृत्व प्रदान किया। वन्देमातरम का नारा लगाने पर कठोर यातना और बेतों की सजा मिलने के बावजूद भी स्व प्यारेलाल'भारत माता'की आराधना में निरंतर लगे रहे। इसी के फलस्वरूप आगे चलकर स्वतंत्र भारत की राजनीति को दिशा देने का महत्तवपूर्ण कार्य इनके हाथों हुआ।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों को दी नवरात्र पर्व की बधाई

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिशक्ति के आराधना पर्व नवरात्र प्रारंभ होने पर प्रदेश के नागरिकों को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कामना की है कि माता रानी की सभी पर कृपा हो और समस्त प्रदेशवासियों के कष्ट दूर हों। कोरोना के कष्ट पूरे विश्व ने गत डेढ़ वर्ष में देखे हैं। ऐसी महामारी से मानवता की रक्षा हो। हम सभी इसके प्रति सजग भी बने रहें। नवरात्रि नई खुशियां लाए। मध्यप्रदेश और देश के साथ ही समस्त विश्व में प्रेम और सद्भाव बढ़े। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नागरिकों के सुखी और समृद्ध होने की कामना की है।

हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई आज

भोपाल । पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान अपना पक्ष मतबूती रखने की सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने तैयारी की है। वहीं बताया जा रहा है कि सात अक्टूबर को स्टेट बार कौंसिल द्वारा राज्य व्यापी प्रतिवाद दिवस की अपील की है तो कोर्ट सुनावई की तारीख आगे बढ़ा सकती है। पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने समय का अभाव होने पर अगली तारीख लगा दी थी।

सीएम ने अरविंद त्रिवेदी के निधन पर शोक जताया

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभिनेता अरविंद त्रिवेदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री चौहान ने कहा कि श्री अरविंद त्रिवेदी ने रामायण धारावाहिक में अपने जीवंत अभिनय से दर्शकों के हृदय में अमिट छाप छोड़ी। वे असाधारण अभिनेता थे। श्री चौहान ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

प्रदेश की राशन दुकानों पर आज मनेगा अन्न उत्सव प्रधानमंत्री मोदी को भेजेंगे सौ-सौ धन्यवाद पत्र

भोपाल । भाजपा के सेवा और समर्पण अभियान के अंतिम दिन 07 अक्टूबर को प्रदेश की सभी राशन दुकानों पर अन्न उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश की सभी 25,435 राशन दुकानों पर उत्सव आयोजित किए जाएंगे, साथ ही प्रत्येक दुकान के हितग्राहियों द्वारा लिए गए 100-100 धन्यवाद पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाए जाएंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता हितग्राहियों का स्वागत करेंगे। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में पिछले अन्न उत्सव के दौरान एक दिन में 25 लाख लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण कर रिकॉर्ड बनाया गया था। प्रदेश सरकार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुरुवार, 07 अक्टूबर को होने वाले अन्न उत्सव को भी सफल बनाएंगे। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महिला मोर्चा की बहनें भी प्रत्येक राशन दुकान पर उपस्थित रहेंगी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक दुकान के हितग्राहियों द्वारा लिए गए 100-100 धन्यवाद पत्र प्रधानमंत्री श्री मोदी तक पहुंचाने में सहायता करेंगे।

प्रदेश में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी

विवाह में 300 और अंतिम संस्कार में 200 व्यक्ति हो सकेंगे शामिल

15 अक्टूबर से पूर्ण क्षमता से खुलेंगे कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट, क्लब ,जिम, फिटनेस सेंटर और योगा केंद्र

भोपाल (एजेंसी)। गृह विभाग ने बुधवार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार विवाह में दोनों पक्षों के कुल 300 और अतिंम संस्कार में 200 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक चल समारोह या जिसमें भी जनसमूह एकत्र होता है, ऐसे सभी आयोजन पर प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के दायरे में आने वाले आठ जिलों में 29 सितंबर को जारी दिशा-निर्देश ही लागू रहेंगे। प्रदेश में रात 11 से सुबह 6.00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा ।

किस पर प्रतिबंध और क्या खोला गया

- सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक चल समारोह आदि, जिसमें भी जनसमूह एकत्र होता है , ऐसे सभी आयोजन पर प्रतिबंधित रहेगा। राजनैतिक कार्यक्रमों के लिए लोकसभा-विधानसभा उपचुनाव से संबधित आठ जिलों में 29 सितंबर को जारी दिशा-निर्देश ही लागू रहेंगे।
- समस्त कोचिंग संस्थान एंव प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 फीसदी की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। 15 अक्टूबर 2021 से 100 फीसदी क्षमता के साथ कोचिंग एंव प्रशिक्षण संस्थान संचालित होंगे। कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थानों के संचालकों करना जरूरी होगा। समस्त धार्मिक, पूजा स्थल की क्षमता से 50 फीसदी की उपस्थिति की सीमा निर्धारित की गई है।
- सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजि कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एंव थियेटर कुल क्षमता के 50 फीसदी की उपस्थिति के साथ संचालित किए जा सकते है। सभी को कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना होगा।
- समस्त प्रकार के उद्योग पूर्ण क्षमता के साथ संचालित होंगे।
- जिम, फिटनेस सेंटर ,योगा केंद्रों को संचालन 15 अक्टूबर से 100 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे।
- स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल को खोला जा सकता है, लेकिन खेल आयोजनों में 50 फीसदी ही दर्शकों की उपस्थिति की बाध्यता रहेगी।
- सभी रेस्टोरेंट एंव क्लब 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना ही होगा।
- एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर यात्रा के लिए व्यक्ति स्वंत्रत होंगे। साथ मालवाहक वाहन भी राज्य में आवागमन कर सकते है।
- गरबा का आयोजन सोसायटियों, कॉलोनियों, मोहल्लों में सिर्फ स्थानीय नागरिकों द्वारा ही 50 फीसदी क्षमता की उपस्थिति में किया जा सकता है। आयोजन की सूचना जिला कलेक्टर को देना होगी। बड़े और व्यावसायिक स्तर के गरबा आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
- किसी प्रकार के आयोजनों, समारोहों में डीजे, बैंडबाजे की अनुमति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही दी जाएगी। जिसमें रात दस बजे तक ही डीजे, बैंडबाजे या अन्य साउंड सिस्टम का उपयोग कर सकते है।
- रावण दहन के पूर्व श्रीराम के चल समारोह को प्रतिकात्मक रूप से ही निकाला जा सकता है। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क और सोशल डिस्टेसिंग की शर्त पर आयोजन समिति को जिला कलेक्टर स्वयं के विवेकानुसार अनुमति दे सकते हैं। रामलीला का आयोजन मैदान या हॉल की कुल क्षमता से 50 फीसदी दर्शक ही शामिल होंगे। रावण दहन के बड़े स्तर पर होने वाले आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी।

लखीमपुर की घटना पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर : डॉ. मिश्रा

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर कांग्रेस का दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया है।

श्री मिश्रा ने बुधवार को यहां मीडिया से चर्चा में कहा कि मौत किसी की भी हो, दुःखद होती है, लेकिन एक मौत पर बोलना और दूसरे पर खामोश रहना संवेदना नहीं, सिर्फ सियासत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन करती है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का विरोध करती है। खंडवा लोकसभा सीट सहित विधानसभा की तीन सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा की पूरी तैयारी है। जल्द ही शुभ मुहूर्त में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा।

मप्र में कोरोना के 128 एक्टिव केस

गृहमंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के 128 एक्टिव केस हैं। श्री मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में कोरोना के कुल एक्टिव केस 128 है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए केस मिले हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 0.02 फीसदी और रिकवरी रेट 98.60 प्रतिशत है।

कश्मीर घाटी में बिंदरु की हत्या पर दुख जताया

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कश्मीर घाटी में माखन लाल बिंदरु की हत्या पर दुख जताया है। श्री मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित माखन लाल बिंदरू जी की निर्मम हत्या का मामला बेहद दुखद और पीड़ादायी है। उन्होंने कहा इस घटना के बाद कांग्रेस का दोहरा चरित्र एक बार फिर सामने आ गया है। श्री मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी छोटी-छोटी घटनाओं पर ट्वीट करते रहते हैं लेकिन इस दुखद घटना पर पूरी तरह खामोश है।

पीजीआई चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित हो भोपाल मेमोरियल अस्पताल

भोपाल (एजेंसी)। भोपाल गैस पीडितों के लिए बनाए गए भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं रिर्सच सेंटर (बीएमएचआरसी) को फिर से अपने पुराने गौरव में लाने के लिए इसे पीजीआई चंडीगढ़ के समान विकसित करने पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है।

दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी

श्री सिंह ने पत्र में बताया है कि बीएमएचआरसी की स्थापना वर्ष 2000 में भोपाल में हुई थी। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित 350 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ने देशभर के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों को आकर्षित किया और भोपाल के गैस पीड़ितों के इलाज में सेवा प्रदान की। पूर्व सीएम ने कहा कि 2010 तक भोपाल में निजी सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना होते रहने से विशेषज्ञ डॉक्टरों को बेहतर तनख्वाह मिलने पर उन्होंने बीएमएचआरसी छोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद नए डॉक्टरों की भी भर्ती की गई, लेकिन वे भी लंबे समय तक अस्पताल में नहीं रह सके। आईसीएमआर द्वारा बीएमएचआरसी को चलाया जा रहा है। अब अस्पताल एक खराब स्थिति में है और सलाहकारों, विशेषज्ञों की भारी कमी से जूझ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा कि अस्पताल के पूर्व गौरव को पुनः बनाए रखने के लिए देश की संसद पीजीआई, चंडीगढ़ व जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी की तर्ज पर एक स्वायत्त पीजी मेडिकल कॉलेज के रूप में नामित कर सकती है। ऐसा करने पर भोपाल मेमोरियल अस्पताल अच्छे डॉक्टरों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके पास पूर्व से ही उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा और उपकरण हैं। उन्होंने कहा कि एक बार के उपाय के रूप में, वर्तमान में अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों को उनकी योग्यता और अनुभव के अनुरूप पदों को प्रस्तावित कर पीजीआई मेडिकल कॉलेज में समाहित किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के साथ कुछ सुझाव प्रस्ताव के रूप में अलग से भेजे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि वे आभारी होंगे यदि वे इस प्रस्ताव को देखकर बीएमएचआरसी के संबंध में संबंधितों को आवश्यक निर्देश दे सकें।

कांग्रेस के उम्मीदवार ने नौ बार विजय हासिल की

खंडवा में भाजपा सात बार जीती, जिसमें नंदू भैया छह बार सांसद चुने गए

भोपाल (एजेंसी)।

मतदाताओं की संख्या

कुल मतदाता	**19,68,389**
पुरुष मतदाता	10,07,135
महिला मतदाता	09,61,184
अन्य मतदाता	70

खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 1952 से 2019 तक कुल 17 चुनाव हुए। इस दौरान भाजपा के उम्मीदवार सात, कांग्रेस के नौ और एक बार भारतीय लोकदल के उम्मीदवार ने विजय हासिल की है। सबसे रोचक बात यह कि भाजपा के स्वार्गीय नेता नंदकुमार चौहान (नंदू भैया) ने इस सीट पर छह बार जीत दर्ज कराई। इसमें 1996 से 2004 तक लगातार चार चुनाव और 2014, 2019 के दोनों चुनाव में विजय हुए। 1996 के बाद से ही खंडवा सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। सिर्फ 2009 में कांग्रेस के अरुण यादव ने भाजपा के नंदकुमार चौहान को हराया था। पिछला 2019 का चुनाव में भाजपा के नंदकुमार चौहान ने दो लाख 73 हजार 343 वोट से जीता था।

मप्र में एक लोकसभा सीट खंडवा और तीन विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के पास बहुत कुछ खोने या पाने के लिए नहीं है। दोनों ही दल उपचुनाव 2021 के माध्यम से वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले जनता की नब्ज को टाटोल रहे हैं। इस उचुनाव के परिणाम बताएंगे कि सत्ता पक्ष से जनता कितनी संतुष्ट या नाराज है और विपक्ष से क्या उम्मीद रख रही है। खंडवा लोकसभा सीट से भाजपा जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी, जबकि कांग्रेस की स्थिति अभी से कमजोर आने लगी है। खंडवा सीट से 2009 में भाजपा उम्मीदवार को हरा चुके अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। स्थानीय तौर पर कांग्रेस टिकट वितरण में ही कई खेमों में बंटी नजर आई। इसका नुकसान चुनाव में हो सकता है। कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा सीट से राजनारायण सिंह पुरनी को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने अभी उम्मीदवार की अधिकृत घोषणा नहीं की है।

आठ विधानसभा सीट में चार एसटी आरक्षित : खंडवा लोकसभा सीट में कुल आठ विधानसभा सीट आती हैं। जिसमें मांधाता, बुरहानपुर, बड़वाह, बागली, पंधाना, नेपानगर, भीकनगांव और खंडवा शामिल है। इनमें से बागली, पंधाना, नेपानगर, भीकनगांव सीटें अनुसूचित जनजाति और खंडवा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है।

2019 के चुनाव में दो लाख 73 हजार से जीते थे नंदू भैया

भाजपा के उम्मीदवार नंदकुमार सिंह चौहान (नंदू भैया) को 8,38,909 मत मिले थे, उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण यादव को दो लाख 73 हजार 343 वोट से हारया था। कांग्रेस के अरुण यादव को 5,65,566 वोट मिले और तीसरे स्थान पर बसपा के दयाराम कोरकू (ठाकुर दादा) को 14,888 मत प्राप्त हुए थे।

सबसे कम वोट से जीते थे कांग्रेस के जी. दीक्षित

1967 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जी. दीक्षित को कुल एक लाख 25 हजार 236 वोट मिले थे, उन्होंने यह चुनाव सिर्फ एक हजार 698 मत से जीता था। उनसे बीजेएस उम्मीदवार एम. भट्ट हार गए थे। एम. भट्ट को एक लाख 23 हजार 538 वोट प्राप्त हुए थे। इसी तरह सबसे अधिक वोटों से भाजपा के उम्मीदवार नंदकुमार चौहान ने पिछला चुनाव 2019 में दो लाख 73 हजार 343 वोट से जीता था।

खंडवा लोस के रहे चुनाव परिणाम

वर्ष	विजयी प्रत्याशी	पार्टी
1952	बाबूलाल तिवारी	कांग्रेस
1957	बाबूलाल तिवारी	कांग्रेस
1962	महेश दत्ता मिश्रा	कांग्रेस
1967	गंगाचरण दीक्षित	कांग्रेस
1971	गंगाचरण दीक्षित	कांग्रेस
1977	परमानंद जिवाला	भालोद
1980	ठाकुर शिवकुमार सिंह	कांग्रेस
1984	कालीचरण सकारगे	कांग्रेस
1989	अमृतलाल तारवाला	भाजपा
1991	ठाकुर महेंद्रकुमार सिंह	कांग्रेस
1996	नंदकुमार सिंह चौहान	भाजपा
1998	नंदकुमार सिंह चौहान	भाजपा
1999	नंदकुमार सिंह चौहान	भाजपा
2004	नंदकुमार सिंह चौहान	भाजपा
2009	अरुण सुभाषचंद्र यादव	कांग्रेस
2014	नंदकुमार सिंह चौहान	भाजपा
2019	नंदकुमार सिंह चौहान	भाजपा

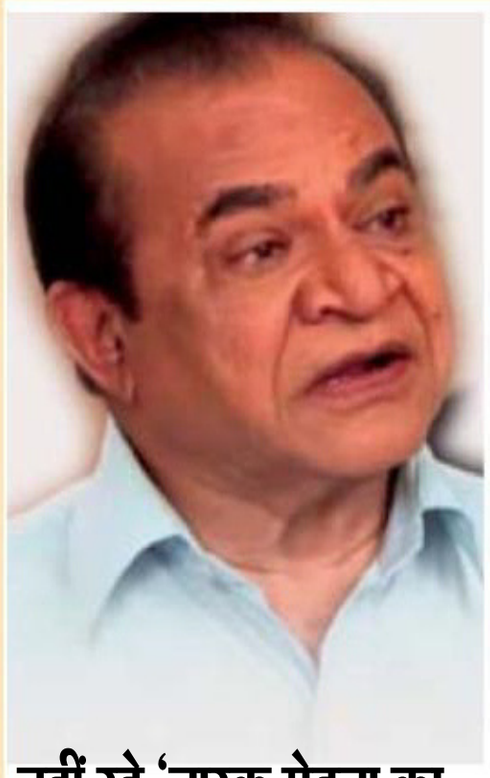

नहीं रहे 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के नट्टू काका, कैंसर के कारण हुआ निधन

नट्टू काका के रोल में सालों तक सभी का मनोरंजन करने वाले 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के घनश्याम नायक का (3 अक्टूबर) को निधन हो गया। ईटाइम्स टीवी की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार अनुभवी अभिनेता, जो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और कीमोथेरेपी से गुजर रहे थे का निधन हो गया। इस खबर से 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो की पूरी कास्ट और क्रू बेहद दुखी और सहमे हुए है। 3 अक्टूबर शाम 5 :30 बजे दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। ईटाइम्स टीवी ने रोशन कौर सोढ़ी की भूमिका निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा, 'हमें अभी इस खबर के बारे में पता चला और यह बेहद दुख की बात है कि हमने उन्हें खो दिया है।'

सोमवार सुबह परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के दौरान तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकारों सहित उनकी पूरी चालक टीम मौजूद रही। असित मोदी, भव्य गांधी, दिलीप जोशी, समय शाह और अन्य को अंतिम विदाई देने के लिए घनश्याम नायक के अंतिम संस्कार में देखा गया। दिलीप जोशी उर्फ जेठालाल श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अभिनेता दिलीप जोशी, जिन्होंने जेठालाल की भूमिका निभाई, सोमवार सुबह घनश्याम नायक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

बग्गा की भूमिका निभाने वाले तन्मय वेकेरिया ने कहा, 'मुझे सबसे पहले खबर मिली क्योंकि उनके बेटे ने मुझे शाम 5 :45 बजे फोन किया था। कुछ महीने पहले अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी हालत में सुधार नहीं हो पाया। उनका आज शाम 5-30 बजे निधन हो गया। तन्मय ने आगे कहा, वह एक रत्न थे और मेरे सबसे करीब थे। उन्होंने हमारे साथ फिर से काम करने की पूरी कोशिश की लेकिन उनके स्वास्थ्य ने अनुमति नहीं दी। मुझे उनके चले जाने का बहुत दुख है। घनश्याम नायक उर्फ नट्टू काका भी दिलीप जोशी के बेहद करीब थे। शो में बग्गा (तन्मय वेकेरिया) और दिलीप जोशी के साथ उनके अधिकतम दृश्य थे, क्योंकि उन्होंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया था।

फिल्म 'रक्षा बंधन' की शूटिंग के लिए चांदनी चौक जा कई यादें ताजा हो गईं: अक्षय कुमार

अभिनेता अक्षय कुमार ने सोमवार को कहा कि उनकी आने वाली फिल्म 'रक्षा बंधन' के लिए उनके जन्मस्थल दिल्ली के चांदनी चौक में शूटिंग करने से उनकी ''कई यादें'' ताजा हो गईं। निर्देशक आनंद एल राय की इस फिल्म के लिए कुमार ने रविवार से दिल्ली में शूटिंग शुरू की। इससे करीब दो महीने पहले मुंबई में फिल्म की शूटिंग पूरी की गई थी। अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्वीट किया '' आज सुबह 'रक्षा बंधन' के सेट पर पहुंचने पर कई यादें ताजा हो गईं, क्योंकि यह मेरे जन्मस्थल चांदनी चौक में है। आसपास लोगों की बातें सुनना कितना अच्छा लगता है ....'' फिल्म 'रक्षा बंधन' में अभिनेत्री भूमि पेडनेकर भी नजर आएंगी। फिल्म के 11 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने की संभावना है।

फाइटर में रितिक रोशन के साथ जोरदार एक्शन करती नजर आएंगी दीपिका पादुकोण

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फिल्म 'फाइटर' में रितिक रौशन के साथ जोरदार एक्शन करती नजर आने वाली हैं। बॉलीवुड निर्देशक सिद्धार्थ आनंद, रितिक रोशन और दीपिका पादुकोण को लेकर फिल्म, 'फाइटर' बना रहे हैं। फिल्म 'फाइटर' भारत की पहली एरियल एक्शन फ्रैंचाइजी है।

कहा जा रहा है कि इस फिल्म में दीपिका भी रितिक के साथ कई एक्शन सीन करती नजर आएंगी। सिद्धार्थ आनंद ने कहा, रितिक और दीपिका के साथ एक्शन में सीन शूट करना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर 'वॉर' के बाद। दीपिका के ऋतिक के साथ जुड़ने से हमें एक्शन का पैमाना बढ़ाना होगा।

उन्होंने कहा, फिल्म 'वॉर' के ब्लॉकबस्टर साबित होने के बाद, इंडिया में 'फाइटर' को लेकर दर्शकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। एक्शन डिजाइन करने के लिए हॉलीवुड तकनीशियनों के साथ काम करना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे यहां भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमें क्या चाहिए। मैं अपनी भारतीय प्रतिभा के साथ काम करना पसंद करूंगा।

सिद्धार्थ आनंद ने कहा, फिल्म 'फाइटर' भारतीय वायुसेना के बारे में है, इसलिए हमने एक्शन को जितना हो सके असली दिखाने पर काम किया है। यह फिल्म दीपिका और ऋतिक के हर फैन को खुश कर देगी। अगले साल की शुरुआत में शूटिंग शुरू करेंगे। हम जल्दी में नहीं हैं। हम सिर्फ दर्शकों को एक ऐसा अनुभव देना चाहते हैं जो उनके होश उड़ा दे और उन्हें सिनेमाघरों में वापस आने पर मजबूर कर दे।

विद्युत जामवाल ने 'खुदा हाफिज चैप्टर 2 - अग्नि परीक्षा' की शूटिंग लखनऊ में की पूरी

बॉलीवुड के माचो हीरो विद्युत जामवाल ने 'खुदा हाफिज चैप्टर 2 – अग्नि परीक्षा' की शूटिंग लखनऊ में पूरी कर ली है। खुदा हाफिज 2 में विद्युत जामवाल के साथ शिवालिका ओबेरॉय मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। लखनऊ में शूटिंग के अनुभव के बारे में बात करते हुए, निर्देशक फारुक कबीर ने कहा, मुझे कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने लखनऊ में बहुत ही बेहतरीन समय बिताया है। हम करीब दो महीने से एक परिवार की तरह रह रहे थे। फिल्म से जुड़ी टीम निर्धारित किए गए समय के अंतर्गत शूटिंग पूरी करने का पूरा प्रयत्न कर रही थी। फिल्म से जुड़े सभी लोगों को यह भरोसा है की वे बहुत जल्द दर्शकों के समक्ष एक प्यारी सी इंटेंस एक्शन लव स्टोरी लेकर आएंगे। गौरतलब है कि पैनोरामा स्टूडियोज़ इंटरनेशनल द्वारा प्रस्तुत खुदा हाफिज चैप्टर 2 कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक द्वारा निर्मित और संजीव जोशी, आदित्य चौकसी और हसनैन हुसैनी द्वारा सहनिर्मित की जा रही है। इस फिल्म में विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबेरॉय ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो परिस्थितियों और समाज द्वारा उत्पन्न की गई चुनौतियों का सामना करते है। यह एक इंटेंस एक्शन लव स्टोरी फिल्म हैं।

क्या देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी ने तीसरी बार रचाई शादी? तस्वीरें हो रही वायरल

टीवी के राम और सीता गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी इंडस्ट्री के पावर कपल में से एक है। दोनों की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते हैं। इन दिनों यह कपल कोलकाता में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, जहां से दोनों कई खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं। हाल ही में देबिना और गुरमीत ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों को देख ऐसा लग रहा है कि ये कपल एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गया है। तस्वीर में गुरमीत क्रीम कुर्ते और व्हाइट धोती में नजर आ रहे हैं। उन्हें सिर पर मुकुट, गले में फूलों का हार पहना हुआ है।

वहीं देबिना लाल रंग के दुल्हन के लिबास में सजी नजर आ रही हैं। उनके सिर पर मुकुट, कुमकुम से सजा माथा, गले में फूलों का हार दिख रहा है। तस्वीर में गुरमीत और देबिना शादी के मंडप में बैठे नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। कई फैंस कमेंट सवाल पूछ रहे हैं कि क्या देबिना और गुरमीत तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे हैं? बता दें कि साल 2006 में परिवार वालों से छुपकर गुरमीत और देबिना ने पहली बार शादी की थी। जब शादी के बारे में परिवार वालों को पता चला तो, घर वालों को मना कर दोनों ने साल 2011 में फिर से शादी की थी। इस शादी की सभी रस्में परिवार वालों की मौजूदगी में निभाईं गई। बंगाल की रहने वाली एक्ट्रेस देबिना से गुरमीत की पहली मुलाकात मुंबई में हुई थी। दोनों ने सीरियल रामायण में एक साथ काम किया था।

आर्यन खान से पहले ये बॉलीवुड सितारें भी फंस चुके हैं ड्रग्स रैकेट में, कुछ को जाना पड़ा जेल

सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद मनोरंजन जगत में चल रहे ड्रग्स रैकेट सामने आ रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी ड्रग्स कनेक्शन में कई बड़े स्टार्स का नाम सामने आ चुका है।

रिया चक्रवर्ती-

सुशांत के निधन के बाद सामने आए ड्रग्स कनेक्शन में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को जेल की हवा खानी पड़ी थीं। पूछताछ के दौरान रिया ने बॉलीवुड के करीब 25 लोगों के नाम का खुलासा किया था जिसमें कई बड़े सितारे भी शामिल थे। रिया ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि वो खुद ड्रग्स लेती थीं।

सारा अली खान-

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान का नाम भी ड्रग्स एंगल में सामने आ चुका है। एनसीबी ने सारा अली खान से पूछताछ की थी। हालांकि एक्ट्रेस ने ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया था।

रकुल प्रीत सिंह-

ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह का नाम भी सामने आया था। एनसीबी ने रकुल को इस मामले में समन भेजा था और पूछताछ की थी। इसके अलावा एनसीबी की टीम साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे ड्रग्स रैकेट में भी सामने आया था।

दीपिका पादुकोण-

सुशांत ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण से भी एनसीबी की टीम ने पूछताछ की थी। खबरों के अनुसार दीपिका और उनकी मैनेजर के व्हाटसएप चैट में ड्रग्स संबंधित बातचीत पाई गई थी।

अरमान कोहली-

ड्रग्स मामले में अभिनेता अरमान कोहली का नाम भी सामने आ चुका है। ड्रग्स मामले में अरमान को जेल भी जाना पड़ा था। अरमान के घर से कोकिन बरामद हुई थी।

भारती सिंह-

कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को भी ड्रग्स केस में जेल जाना पड़ा था। एनसीबी को छापेमारी के दौरान भारती के घर से गांजा बरामद हुआ था। बाद में पूछताछ में भारती सिंह और हर्ष दोनों ने ही यह कबूला था कि वे गांजे का सेवन करते रहे हैं।

गौरव दीक्षित-

टीवी एक्टर गौरव दीक्षित को भी ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गौरव के घर से कुछ समय पहले छापेमारी के दौरान एमडी ड्रग्स चरस और दूसरे ड्रग्स बरामद किए गए थे।

श्रद्धा कपूर-

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से भी एनसीबी पूछताछ कर चुकी हैं। श्रद्धा कपूर सीबीडी आईल का सेवन कर रही थीं जो कि ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। पूछताछ के दौरान एक्ट्रेस ने बताया था कि वह इस आईल का सेवन एक्सटर्नल यूज के लिए करती थीं।

प्लेऑफ की दौड़ में आगे रहने के लिए केकेआर की निगाहें राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बड़ी जीत पर

एजेंसी ■ शारजाह

दो बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स गुरूवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग के अंतिम राउंड रोबिन मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने का प्रयास करेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) 13 मैचों में 12 अंक के साथ इस समय तालिका में चौथे स्थान पर बनी हुई है। वह गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस से नेट रन रेट के हिसाब से आगे है। मुंबई इंडियंस के भी 13 मैचों में 12 अंक हैं और उसे शुक्रवार को निचले स्थान पर काबिज सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक मैच खेलना है। अगर दोनों केकेआर और मुंबई इंडियंस अपने अंतिम मैच जीत जाते हैं तो फिर फैसला नेट रन रेट से होगा इसलिए इयोन मोर्गन की अगुआई वाली टीम (0.294) बढ़त बनाना चाहेगी क्योंकि इस समय उसका रन रेट पॉजिटिव है जबकि मुंबई की टीम (-0.048) रन रेट नेगेटिव है। केकेआर को टूर्नामेंट के दूसरे चरण में मिश्रित नतीजे मिले हैं जिसमें से उसने चार मैचों में जीत हासिल की जबकि दो में उसे हार का सामना करना पड़ा। केकेआर ने अपना अभियान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगातार दो जीत से शुरु किया जिसके बाद उसे चेन्नई सुपर किंग्स से हार का सामना करना पड़ा लेकिन उसने तालिका पर शीर्ष पर चल रही दिल्ली कैपिटल्स पर जीत दर्ज कर वापसी की। पंजाब किंग्स के खिलाफ हार के बाद उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को छह विकेट से हराकर अंतिम प्लेऑफ स्थान के लिए दौड़ में खुद को आगे बनाए रखा। दूसरे चरण में केकेआर का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है और यहां तक कि उसे जिन दो मैचों में हार मिली, वो भी करीबी मुकाबले रहे जिसमें उसे अंतिम ओवर में पराजय मिली। बल्लेबाजी विभाग में वेंकटेश अय्यर केकेआर के लिए दूसरे चरण में स्टार खिलाड़ी रहे जबकि राहुल त्रिपाठी भी इस सत्र में काफी प्रभावशाली रहे। युवा शुभमन गिल ने केकेआर के पिछले मैच में शानदार अर्धशतक जमाया जो टीम के लिए अच्छा संकेत है। बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष पर नितीश राणा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन उसके लिए कप्तान मोर्गन की फॉर्म चिंता का विषय है। बांग्लादेश के स्टार आल राउंडर शाकिब अल हसन को पिछले मैच में शामिल किया गया और यह दूसरे चरण में पहली बार हुआ जिससे टीम को नया आयाम मिला। गेंदबाजी में रहस्यमई स्पिनर वरूण चक्रवर्ती टीम के अहम खिलाड़ी रहे हैं जबकि सुनील नारायण ने भी विकेट चटकाए हैं।

टीमें इस प्रकार हैं :

कोलकाता नाइट राइडर्स : इयोन मोर्गन (कप्तान), दिनेश कार्तिक, गुरकीरत सिंह मान, करुण नायर, नितीश राणा, राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल, हरभजन सिंह, कमलेश नागरकोटी, कुलदीप यादव, लॉकी फर्ग्युसन, पवन नेगी, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप वारियर, शिवम दुबे, टिम साउथी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसेल, बेन कटिंग, शाकिब अल हसन, सुनील नारायाण, वेंकटेश अय्यर, शेल्डन जैक्सन, टिम सीफर्ट।

राजस्थान रॉयल्स : संजू सैमसन (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, एविन लुईस, डेविड मिलर, क्रिस मॉरिस, ओशाने थॉमस, मुस्ताफिजुर रहमान, तबरेज शम्सी, ग्लेन फिलिप्स, चेतन सकारिया, रियान पराग, राहुल तेवतिया, आकाश सिंह, अनुज रावत, केसी करियप्पा , यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, कार्तिक त्यागी, मयंक मार्कंडे, जयदेव उनादकट, कुलदीप यादव, महिपाल लोमरोर।

मैच का समय : शाम 7.30 से।

टी20 श्रृंखला से आस्ट्रेलियाई दौरे का सकारात्मक अंत करने उतरेगी भारतीय टीम

एजेंसी ■ गोल्ड कोस्ट

कप्तान हरमनप्रीत कौर की वापसी से उत्साहित भारतीय महिला क्रिकेट टीम मजबूत आस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार से शुरू होने वाली तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला में जीत दर्ज करके इस दौरे का सकारात्मक अंत करने की कोशिश करेगी। हरमनप्रीत अंगूठे की चोट के कारण एकदिवसीय श्रृंखला और एकमात्र दिन रात्रि टेस्ट मैच में नहीं खेल पाई थी लेकिन अब वह फिट हैं जिससे टीम की बल्लेबाजी का आक्रामक पक्ष मजबूत हुआ है जिसमें युवा शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी शानदार फॉर्म में चल रही है। आस्ट्रेलियाई दौरे के आखिरी चरण के मैचों से पहले मंधाना आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही अपना पहला टेस्ट शतक लगाया था। यह सीनियर बल्लेबाज निश्चित तौर पर उस लय को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध होगी हालांकि दोनों प्रारूपों में बहुत अंतर है। हरमनप्रीत की वापसी टीम के लिए अच्छा संकेत है लेकिन सभी की निगाह युवा शेफाली पर टिकी रहेंगी जो आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जानी जाती है। इस दौरे के दौरान भारतीय टीम ने दिखाया कि वह कुछ समय के अंदर ही विभिन्न प्रारूपों से सामंजस्य बिठा सकती है। इससे वे गुलाबी गेंद से खेले गए टेस्ट में भी दबदबा बनाने में सफल रही। इससे पहले उसने वनडे में आस्ट्रेलिया का 26 जीत का अभियान थामा था। हरमनप्रीत के लिए चोट बड़ा झटका था लेकिन अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप से पहले उनके लिए यह टी20 श्रृंखला बेहद महत्वपूर्ण होगी। वह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में मैच विजेता है और वह इन मैचों में कोई मौका नहीं गंवाना चाहेंगी। आस्ट्रेलियाई गेंदबाज शेफाली, मंधाना और हरमनप्रीत को निशाने पर रखेंगे जबकि युवा जेमिमा रोड्रिग्स को अपनी फॉर्म हासिल करने के लिए एक और मौका मिलेगा।

टीमें इस प्रकार हैं :

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप कप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, यास्तिका भाटिया, शिखा पांडे, मेघना सिंह, पूजा वस्त्राकर, राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम यादव, ऋचा घोष (विकेटकीपर), हरलीन देओल, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, रेणुका सिंह।

आस्ट्रेलिया: मेग लैनिंग (कप्तान), डार्सी ब्राउन, मैटलन ब्राउन, स्टेला कैंपबेल, निकोला कैरी, हन्ना डार्लिंगटन, एशले गार्डनर, एलिसा हीली, ताहलिया मैक्ग्रा, सोफी मोलिनक्स, बेथ मूनी, एलिस पैरी, जॉर्जिया रेडमायने, मौली स्ट्रानो, एनाबेल सदरलैंड, टायला व्लामिनक, जॉर्जिया वेयरहैम।

मैच दोपहर बाद दो बजकर 10 मिनट से शुरू होगा।

एक नजर

जर्मनी के पूर्व कप्तान लाम ने दो वर्ष में विश्व कप आयोजन का विरोध किया

बर्लिन। जर्मनी के पूर्व कप्तान फिलिप लाम ने विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा के हर दो वर्ष में विश्व कप आयोजित करने की योजना का विरोध किया है। लाम ने कहा, मेरा मानना है कि वर्तमान व्यवस्था पूर्ववत बनी रहनी चाहिए। मैं मानता हूं कि एक खिलाड़ी के रूप में आप हर दो वर्ष में टूर्नामेंट की उम्मीद कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि अन्य प्रतियोगिताओं को भी सुर्खियों में रहने का अधिकार है। उन्होंने कहा, इसलिए मैं वर्तमान व्यवस्था को बरकरार रखने के पक्ष में हूं। एक खिलाड़ी केलिए भी यह सहज व्यवस्था है। मैं इस बारे में केवल अपने विचार रख सकता हूं। लाम ने यूरो 2024 के प्रतीक चिन्ह को जारी किए जाने के अवसर पर आयोजित समारोह में कहा, एक प्रशंसक के तौर पर मुझे लगता है कि इस तरह की प्रमुख प्रतियोगिताओं का हर दो वर्ष (विश्व कप या यूरो में से कोई एक) में आयोजन अच्छा है और इसलिए मैं चीजों को वर्तमान की तरह बनाए रखने के पक्ष में हूं।

यह देखना अच्छा है कि इंग्लैंड की टीम आ रही है: फिंच

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान आरोन फिंच ने कहा कि उन्हें यह देखकर अच्छा लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम साल के अंत में एशेज दौरे के लिए आ रही है। खबरों के अनुसार इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और अन्य खिलाड़ियों ने एशेज दौरे के लिए अपनी सहमति दे दी है। आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए अपनी टीम के संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना होने से पहले फिंच ने बुधवार को कहा, मैं पूरी तरह से उनके साथ सहानुभूति रखता हूं, उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त है। इंग्लिश मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार कुछ खिलाड़ियों ने क्रिकेट आस्ट्रेलिया के अधिकारियों से बात की थी और वे अपने और अपने परिवार के लिए लगाई गई बायो-बबल शर्तों से संतुष्ट हैं। इससे पहले इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा था

संक्षिप्त खबर

सैफ चैम्पियनशिप : श्रीलंका के खिलाफ टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज करना चाहेगा भारत

एजेंसी ■ माले

बांग्लादेश की 10 खिलाड़ियों की टीम से।-। से ड्रा खेलने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम के आत्मविश्वास पर असर पड़ा होगा लेकिन टीम जल्द ही इससे उबरकर गुरूवार को यहां श्रीलंका के खिलाफ सैफ चैम्पियनशिप के दूसरे मैच में जीत दर्ज करना चाहेगी। भारत को बांग्लादेश के खिलाफ पिछले मैच में निराशा हाथ लगी जिसके खिलाफ उसने ज्यादातर समय दबदबा बनाया हुआ था और कप्तान सुनील छेत्री की बदौलत बढ़त भी हासिल कर ली थी जिसे देखते हुए उसे जीत दर्ज करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका जिससे भारतीय टीम टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज करने के लिए बेताब होगी। श्रीलंका के खिलाफ उसने रिकार्ड सात बार जीत हासिल की है। ब्लू टाइगर्स के मुख्य कोच इगोर स्टिमक हाल में भारत के मैचों में जीत दर्ज करने में विफलता के कारण आलोचनाओं से घिरे हुए हैं और गुरूवार को वह काफी दबाव में होंगे। बांग्लादेश के खिलाफ निराशा के बावजूद भारत को निचली रैंकिंग की श्रीलंकाई टीम के खिलाफ जीत का भरोसा है जो अभी तक टूर्नामेंट में जूझती नजर आई है। उसने अभी तक दोनों मैच गंवाए हैं जिसमें उसने चार गोल खाए और दो गोल किए हैं। छेत्री ने पिछले मैच में भारत को बढ़त दिला दी थी जिसके बाद बांग्लादेश के बिश्वनाथ घोष को दूसरे हाफ में रेड कार्ड दिखा दिया गया।

भारतीय टीम

धीरज सिंह, विशाल कैथ, गुरप्रीत सिंह संधू, प्रीतम कोटल, विंग्लेनसाना सिंह कोनशाम, मंदर राव देसाई, राहुल भेके, सुभाशीष बोस, शेरिटोन फर्नांडिज, उदांता सिंह, ब्रैंडन फर्नांडिज, लालेंगमाविया, अनिरूद्ध थापा, सहल अब्दुल समद, जैक्सन सिंह, ग्लान माटिन्स, सुरेश सिंह, लिस्टन कोलासो, यासिर मोहम्मद, मनवीर सिंह, रहीम अली, सुनील छेत्री, फारूख चौधरी में से।

मैच भारतीय समयानुसार शाम साढ़े चार बजे से शुरू होगा।

सनराइजर्स ने आरसीबी को 142 रन का लक्ष्य दिया

एजेंसी ■ अबुधाबी

तेज गेंदबाज हर्षल पटेल और डैन क्रिस्टियन की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को यहां सनराइजर्स हैदराबाद को सात विकेट पर 141 रन के स्कोर पर रोक दिया। हर्षल पटेल (33 रन पर तीन विकेट), क्रिस्टियन (14 रन पर दो विकेट) और युजवेंद्र चहल (27 रन पर एक विकेट) की प्रभावी गेंदबाजी के सामने हैदराबाद के बल्लेबाज बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहे। अहमद और मोहम्मद सिराज ने किफायती गेंदबाजी करते हुए क्रमशः चार और तीन ओवर में 21 और 17 रन दिए लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। हैदराबाद की ओर से जेसन रॉय (44) और कप्तान केन विलियमसन (31) के अलावा कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी भी की। हैदराबाद के बल्लेबाज अंतिम आठ ओवर में 50 रन ही जोड़ पाए। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर हैदराबाद की टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। अभिषेक शर्मा (13) ने दूसरे ओवर में जॉर्ज गार्टन की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का मारा। चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने फाइन लेग पर उनका कैच टपकाया लेकिन अगली गेंद पर वह ग्लेन मैक्सवेल को मिड आन कैच दे बैठे। विलियमसन ने सिराज पर दो चौकों के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज रॉय ने भी गार्टन पर चौका जड़ा। हैदराबाद की टीम ने पावर प्ले में एक विकेट पर 50 रन बनाए। बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज और लेग स्पिनर चहल ने रन गति पर विराम लगाया। रॉय और विलियमसन ने बीच में कुछ अच्छे शॉट खेले।

पंजाब किंग्स के खिलाफ चेन्नई का पलड़ा भारी

एजेंसी ■ दुबई

अंकतालिका में शीर्ष पर पहुंच बनाने की कवायद में लगा चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में गुरुवार को यहां पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाले मैच में मजबूत दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम का लगातार दो हार के बावजूद पंजाब पर पलड़ा भारी नजर आता है जो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के कगार पर है। पिछले साल के लचर प्रदर्शन को भुलाकर इस वर्ष शानदार वापसी करने वाली चेन्नई की टीम ने यूएई चरण में अच्छा प्रदर्शन किया है और उसे हराना आसान नहीं है। चेन्नई के बल्लेबाज अच्छी लय में हैं विशेषकर रुतुराज गायकवाड़। उसके बल्लेबाज इस प्रदर्शन को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गायकवाड़ और दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस ने शीर्ष क्रम में अच्छा खेल दिखाया है जबकि अंबाती रायुडु ने मध्यक्रम में उपयोगी योगदान दिया है। मोइन अली ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन सुरेश रैना और धोनी की खराब फॉर्म चेन्नई के लिए चिंता का सबब है। रविंद्र जडेजा ने फिर से एक आलराउंडर के तौर पर अपनी उपयोगिता साबित की है और उपयोगी योगदान दिया है।

टीमें इस प्रकार हैं

चेन्नई सुपर किंग्स: महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), सुरेश रैना, अंबाती रायुडू, केएम आसिफ, दीपक चाहर, ड्वेन ब्रावो, फाफ डु प्लेसिस, इमरान ताहिर, एन जगदीशन, कर्ण शर्मा, लुंगी एनगिडी, मिशेल सेंटनर, रविंद्र जडेजा, रुतुराज गायक्वाड़, शार्दुल ठाकुर, आर साई किशोर, मोईन अली, के गौतम, चेतेश्वर पुजारा, हरिशंकर रेड्डी, भगत वर्मा, सी हरि निशांत।

पंजाब किंग्स: केएल राहुल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, अर्शदीप सिंह, इशान पोरेल, शाहरुख खान, मोहम्मद शमी, नाथन एलिस, आदिल राशिद, मुरुगन अश्विन, हरप्रीत बराड़, मोइसेस हेनरिक्स, क्रिस जॉर्डन, एडेन मार्कराम, मनदीप सिंह, दर्शन नालकांडे, प्रभसिमरन सिंह, रवि बिश्नोई, उत्कर्ष सिंह, फैबियन एलन, सौरभ कुमार, जलज सक्सेना।

मैच दोपहर बाद तीन बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

आईसीसी के सितंबर महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के नामितों में शामिल हैं जसकरण मल्होत्रा

एजेंसी ■ दुबई

भारत में जन्में अमेरिकी जसकरण मल्होत्रा को बुधवार को सितंबर महीने के आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) के सर्वश्रेष्ठ पुरूष खिलाड़ी के लिए तीन नामांकित क्रिकेटरों में शामिल किया गया जो किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में एक ओवर में छह छक्के जड़ने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। अन्य दो नामांकित खिलाड़ी बांग्लादेश के स्पिनर नासुम अहमद और नेपाल के लेग स्पिनर संदीप लामिचाने हैं। इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट, उनकी हमवतन चार्ली डीन और दक्षिण अफ्रीका की लिजली ली को आईसीसी के महीने की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए नामांकित किया गया है। चंडीगढ़ में जन्में और अंडर-19 स्तर पर हिमाचल प्रदेश की कप्तानी करने वाले 31 साल के मल्होत्रा ने नौ सितंबर को ओमान में विश्व कप लीग 2 के एक मैच में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ नाबाद 173 रन की शानदार पारी के दौरान एक ओवर में छह छक्के जड़े थे। उनके नाम पर छह वनडे में 87 के औसत और 104.40 के स्ट्राइक रेट से 261 रन हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में नासुम अहमद बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी रहे थे जिसमें प्रतिद्वंद्वी टीम उनकी सटीक लाइन एवं लेंथ के झांसे में आ गई थी। उन्होंने इस श्रृंखला में आठ विकेट चटकाए जिसमें चौथे मैच में उनका प्रदर्शन 10 रन देकर चार विकेट था। इस प्रदर्शन की बदौलत मेजबान टीम ने न्यूजीलैंड को 3-2 के अंतर से पराजित कर दिया था। लामिचाने अपने छोटे से करियर में अब तक अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित कर चुके हैं। सितंबर के महीने में भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहा जिसमें वह विश्व कप लीग 2 में बेहतरीन गेंदबाज रहे। छह वनडे में उन्होंने 18 विकेट चटकाए और उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 11 रन देकर छह विकेट लेकर सभी का ध्यान खींचा। महिलाओं में चार्ली डीन न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाली गेंदबाज रहीं। उन्होंने 10 विकेट झटके थे। इससे इंग्लैंड ने श्रृंखला में 4-1 से जीत हासिल की। इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट ने गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 214 रन जोड़े जिसमें पहले और चौथे वनडे में क्रमशः 89 और 101 रन की पारियां खेलीं। उन्होंने तीन विकेट भी झटके। लिजली ली कैरेबियाई सरजमीं पर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे श्रृंखला में 248 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं।

टॉस और पिच का नहीं, अधिक दोष हमारा : संगकारा

एजेंसी ■ शारजाह

राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट निदेशक कुमार संगकारा ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मुंबई इंडियन्स के हाथों करारी हार के लिए अपनी टीम को दोषी ठहराया और कहा कि टॉस और पिच को इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता। जिम्मी नीशाम और नाथन कूल्टर नाइल ने बेहतरीन गेंदबाजी करके रॉयल्स की टीम को नौ विकेट पर 90 रन ही बनाने दिए। मुंबई ने इशान किशन के 25 गेंदों पर नाबाद 50 रन से आठ विकेट से जीत दर्ज करके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें जीवंत रखी। संगकारा से पूछा गया कि क्या टॉस ने अहम भूमिका निभाई, उन्होंने कहा, आप ऐसा कह सकते हैं। हम यहां शारजाह में नहीं खेले थे और अन्य मैचों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि आज यह थोड़ा बेहतर है और संभवतः इसमें थोड़ी तेजी है। उन्होंने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, लेकिन जब आपको केवल 90 रन का बचाव करना होता है तो यह मुश्किल होता है। यह तभी संभव है जबकि आप पावरप्ले में बहुत कम रन देकर कुछ विकेट हासिल करते हो। संगकारा ने कहा, हमारे लिए वह महत्वपूर्ण पल था जब हमने पावरप्ले में 41 रन बनाए थे। हमारी योजना 13 से 14 ओवर तक इसी गति से रन बनाने की थी। हमारे पास सात विकेट बचे थे और हम एक या दो गेंदबाजों को निशाना बनाकर 15वें ओवर के बाद के लिए मंच तैयार कर सकते थे। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से हम परिस्थितियों के अनुरूप नहीं खेल पाए और मुंबई ने बेहतरीन गेंदबाजी की और हमने लगातार विकेट गंवाए इसलिए किसी भी चरण में हम हावी होकर नहीं खेल पाए।

हॉकी भारत के पांच खिलाड़ियो तथा पुरुष और महिला टीमो के मुख्य कोच ने विभिन्न वर्गो मे सर्वाधिक मत पाकर शीर्ष पुरस्कार हासिल किए।

एफआईएच वार्षिक पुरस्कारों में भारतीयों को दबदबा

ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम ने उठाए सवाल

एजेंसी ■ लुसाने

भारत ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के वार्षिक पुरस्कारों में बुधवार को अपना दबदबा बनाया तथा मतदान पर आधारित प्रणाली में सभी वर्गों में शीर्ष पुरस्कार हासिल किए जिसे पुरुष ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम ने पुरस्कारों की विफलता करार दिया। भारत के पांच खिलाड़ियों तथा पुरुष और महिला टीमों के मुख्य कोच ने विभिन्न वर्गों में सर्वाधिक मत पाकर शीर्ष पुरस्कार हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तोक्यो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था जबकि महिला टीम चौथे स्थान पर रही थी। गुरजीत कौर (महिला) और हरमनप्रीत सिंह (पुरुष) ने अपने वर्गों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (प्लेयर ऑफ द ईयर) का पुरस्कार हासिल किया। सविता पूनिया (सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, महिला), पीआर श्रीजेश (सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, पुरुष), शर्मिला देवी (सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार, महिला) और विवेक प्रसाद (सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार, पुरुष) के साथ-साथ भारत की महिला टीम के कोच सोर्ड मारिन और पुरुष टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड भी सर्वाधिक मत पाकर शीर्ष पर रहे। रीड अब भी टीम के साथ बने हुए हैं जबकि मारिन का कार्यकाल तोक्यो खेलों के साथ ही समाप्त हो गया था। ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत और गुरजीत ने अपनी टीमों की तरफ से ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक गोल किए थे। हॉकी बेल्जियम ने विजेताओं की घोषणा होने के बाद इस पर कड़ी प्रतिक्रिया की और पुरस्कारों की प्रक्रिया पर सवाल उठाए क्योंकि तोक्यो खेलों के चैंपियन को एक भी पुरस्कार नहीं मिला। उसने ट्वीट किया, हॉकी बेल्जियम एफआईएच हॉकी स्टार अवार्ड के परिणामों से बेहद निराश है। एक स्वर्ण पदक विजेता टीम जिसके सभी वर्गों में कई नामांकन थे, उसे एक भी पुरस्कार नहीं मिला जिससे मत प्रणाली की विफलता का पता चलता है।

हम भविष्य में एक निष्पक्ष प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए एफआईएच के साथ काम करेंगे। टीम के आधिकारिक हैंडल पर भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की गई हैं। टीम की तरफ से ट्वीट किया गया, हम पूरी तरह से सहमत हैं। यह सामान्य नहीं है। हमारे खेल की विश्वसनीयता और छवि एक बार फिर मुश्किल दौर से गुजर रही है। बेहद अफसोस की बात है। राष्ट्रीय संघों के मतों को कुल परिणाम का 50 प्रतिशत माना गया। राष्ट्रीय संघों का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित राष्ट्रीय कप्तानों और कोच ने किया। इसके अलावा प्रशंसकों और खिलाड़ियों (25 प्रतिशत) तथा मीडिया (25 प्रतिशत) के मतों के आधार पर अंतिम फैसला किया गया। एफआईएच के बयान में बताया गया है कि कुल 79 राष्ट्रीय संघों ने मतदान में हिस्सा लिया। इनमें अफ्रीका के 25 सदस्यों में से 11, एशिया के 33 में से 29, यूरोप के 42 में से 19, ओसेनिया के आठ में से तीन तथा पैन अमेरिका के 30 में से 17 सदस्य शामिल हैं। इसमें कहा गया है, रिकार्ड 300,000 प्रशंसकों ने मतदान किया। एफआईएच हॉकी स्टार्स पुरस्कारों में प्रशंसकों की भागीदारी बेजोड़ रही।